04 - कैसे बढ़े चुनावों में मतदान का प्रतिशत?

05 - ईवीएम सरल, सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024

06 - लोगों को ठगने साइबर ठग अपना रहे नये-नये तरीके...

07 - भोपाल में चौथी लाइन के लिए टूटेंगी झुग्गियां-दुकानें

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-100 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

प्रसंगवश

बांग्लादेश को अब फिर पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए

आमना बेगम

बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह ही भारत के प्रति बढ़ती हुई विदेशी घृणा और राजनीतिक दुश्मनी की लहर चल रही है। बांग्लादेश में कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने फर्श पर भारतीय ध्वज और इस्कॉन का प्रतीक पेंट कर दिया और छात्रों से उस पर चलने को कहा।

शेख हसीना द्वारा चरमपंथी इस्लामी तत्वों को नियंत्रित रखने के प्रयासों के बावजूद, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। हालांकि, उनकी सरकार के पतन के बाद, हिंदुओं का उत्पीड़न काफी बढ़ गया है।

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार, 4 से 20 अगस्त के बीच हिंदुओं पर 2,000 से अधिक सांप्रदायिक हमले हुए। इसमें घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले शामिल हैं। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न की चार खबरें सामने आई हैं, जिनमें सामूहिक बलात्कार का मामला भी शामिल है। अधिकारी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं और दुनिया आखिरकार इस पर ध्यान दे रही है। ब्रिटिश संसद के एक आपातकालीन सत्र के दौरान, सांसद प्रीति पटेल ने बांग्लादेश की स्थिति को 'गंभीर रूप से चिंताजनक' बताया।

यूनुस का जवाबदेही से बचनाः बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने हसीना के पतन के बाद हिंदुओं पर हुए हमलों को स्वीकार किया है, लेकिन अल्पसंख्यक विरोधी भावना की मौजूदगी से इनकार किया है और हमलों को राजनीति से प्रेरित बताया है। यह बयान न केवल राजनीतिक स्किल की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह खतरनाक रूप से इनकार और औचित्य के करीब है। यह समाज के भीतर चरमपंथी तत्वों को एक खतरनाक संदेश भेजता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक संघर्ष की आड़ में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना माफ किया जा सकता है।

यूनुस की बयानबाज़ी पाकिस्तान के ब्लेसफैमी कानूनों के दुरुपयोग को दर्शाती है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से अल्पसंख्यकों को सताने के लिए किया जाता रहा है और फिर भी नेतृत्व द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुखद है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अल्पसंख्यक विरोधी अभियान को कमतर आंकने के अलावा, यूनुस ने भारत पर अफवाहें फैलाने और एक नया बांग्लादेश बनाने के उनकी सरकार के प्रयासों को कमज़ोर करने का भी आरोप लगाया है। हिंसा की विश्वसनीय खबरें सामने आने के बाद से यह बात बेबुनियाद है। यूनुस ने इन शिकायतों को दूर करने के बजाय भारत पर दोष मढ़ना चुना है, जो जिम्मेदारी से बचने का एक सुविधाजनक तरीका प्रतीत होता है।

अंतरिम सरकार को अपने अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों को दूर करने में सक्रिय रुख अपनाना चाहिए था। हिंदुओं पर अत्याचारों का विरोध करने वाले कार्यकर्ता हिंदू संन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी राज्य की प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ बताती है।

दास अपने बचाव के लिए वकील नहीं जुटा पाए, यह बांग्लादेश में व्याप्त अल्पसंख्यक विरोधी भावना के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालांकि, अदालत ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसका अस्तित्व ही ज़मीनी हकीकत को उजागर करता है। उल्लेखनीय रूप से, ऐसी खबरें हैं कि इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण कार्यालय (आईसीपीओ) ने शिकायतों के कारण दास पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच सेना द्वारा सीसीटीवी कैमरे हटाने के वीडियो देखना चिंताजनक है। ऐसी घटनाएं सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी राज्य संस्थाओं की भूमिका पर एक भयावह छाया डालती हैं। जब अल्पसंख्यकों की रक्षा करने वाले ही आतंक का स्रोत बन जाते हैं, तो वह कहां जाएं? अपने ही देश में अलग-थलग महसूस करना दुःखद है – परिचित वर्दी को देखना जो सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए, लेकिन वह भय का प्रतीक है।

बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह ही भारत के प्रति बढ़ती हुई विदेशी घृणा और राजनीतिक दुश्मनी की लहर चल रही है। बांग्लादेश में कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने फर्श पर भारतीय ध्वज और इस्कॉन का प्रतीक पेंट कर दिया और छात्रों से उस पर चलने को कहा।

बच्चों को बढ़ने, सीखने और अपनी राय बनाने के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण मिलना चाहिए। उन्हें अपने से अलग लोगों से डरना या नफरत करना सिखाना विभाजन के बीज बोता है जो सहानुभूति और एकता के लिए आजीवन बाधाओं में बदल जाता है। यह केवल शिक्षा प्रणाली की विफलता नहीं है बल्कि भावनात्मक शोषण का एक रूप है। मासूमियत और नकारात्मकता को हथियार के रूप में इस्तेमाल होते देखना वाकई निराशाजनक है।

जबकि मैं अभी भी बांग्लादेश के लिए आशान्वित हूं, मैं प्रार्थना करती हूं कि इनकार करने और विचलित करने के बजाय, सरकार देश के संस्थापक सिद्धांतों का सम्मान करे, एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त करे। बांग्लादेश का भविष्य उसके वर्तमान नेतृत्व द्वारा बनाए गए मूल्यों से परिभाषित होगा। कोई केवल यह उम्मीद कर सकता है कि आधुनिक बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान का सपना सच न हो।

जब ये परेशान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बांग्लादेशी नेतृत्व और समाज को रुककर सोचना चाहिए- क्या यह वास्तव में एक नए बांग्लादेश का मार्ग है? देश को पाकिस्तान के प्रक्षेपवक्र को देखना चाहिए - जो प्रणालीगत भेदभाव, अल्पसंख्यक अधिकारों के हनन और एक खंडित समाज द्वारा चिह्नित है- और बेहतर फैसला लेना चाहिए। किसी राष्ट्र की महानता इस बात से नहीं मापी जाती है कि वह अपने बहुसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे करता है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मौन बहते अश्रुओं का क्या करूँ?
वर्ष-जितने इन पलों का क्या करूँ?
क्या करूँ जलते हुए अस्तित्व का
और इन बुझते दियों का क्या करूँ?
सुख छबीलों-से मिले हर मार्ग में
तरु-सरीखे इन दुखों का क्या करूँ?
अनवरत चलना रहा, पर आज इन
ढीठ विद्रोही पगों का क्या करूँ?
गीत तो पूरा मुझे कंठस्थ है
भीत कंपित-से स्वरों का क्या करूँ?
मन नहीं लौटा अभी उस लोक से
इस जगत् के उत्सवों का क्या करूँ?

- सुरेन्द्र कुमार वत्स

संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर

11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे, 6 साल से गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। दास का 10 दिसंबर 2024 को कार्यकाल पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे।

पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी स्कीम लॉन्च की

एमएसपी पर फसलें खरीद रहे, हरियाणा ने 'एक हैं तो सेफ हैं' का मंत्र अपनाया

पानीपत (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा सखी योजना लॉन्च की। जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया।

इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम-राम करता हूं, जिन्होंने 'एक हैं तो सेफ हैं' के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया। पीएम ने कहा कि चुनाव दर चुनाव विरोधी परेशान हैं कि मोदी जीत कैसे रहा है।

जयपुर में पीएम मोदी बोले-

राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा है

- राजस्थान राइजिंग तो है ही रिलायबल भी है, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है

जयपुर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- राजस्थान राइजिंग तो है ही रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है। समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिस्पोंसिव रिफॉर्मिव सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहां के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन प्रसन्नता और गर्व का विषय : मुख्यमंत्री

श्रीमद्भगवद्गीता जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का मार्ग है, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन प्रसन्नता और गर्व का विषय है। इस आयोजन को मूर्त रूप देने में हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गीता महोत्सव और गीता जयंती की देशवासियों, प्रदेशवासियों और हरियाणा सरकार को शुभकामनाएं दीं।

प्रदेश में 12 दिसम्बर तक होंगे विविध कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र वही स्थान है, जहां भगवान श्रीकृष्ण द्वारा 5 हजार वर्ष पहले कौरव-पांडवों के युद्ध के बीच अर्जुन को कर्मवाद की शिक्षा प्रदान करने से धर्म ग्रंथ 'गीता' की रचना हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा कर्मवाद की शिक्षा के आधार पर की गई पुस्तक की रचना से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरू जैसे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा लेकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा पवित्र भाव से जीवन के रहस्य की व्याख्या करने वाला संवाद श्रीमद्भगवद्गीता आज भी सबके लिए पाथेय और समसामयिक हैं। हमारे लिए श्रीमद्भगवद्गीता न केवल पवित्र ग्रंथ अपितु जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का मार्ग भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 8 से 12 दिसम्बर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें श्रीमद्भगवद्गीता पर केन्द्रित विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।

राहुल ने मोदी-अडाणी का मुखौटा लगाए सांसदों से बातचीत की, पूछा-

आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है, सांसद बोले- सब मिलकर करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 10वां दिन है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडाणी का मुखौटा पहने सांसदों से बातचीत की।राहुल ने सांसद से पूछा कि आप क्या बोल रहे हो? इस पर अडाणी का मुखौटा पहने सांसद ने कहा कि कुछ भी चाहता हूं। एयरपोर्ट चाहिए। राहुल ने पूछा कि अगला क्या लेने की कोशिश कर रहे हो?

अडाणी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि हमारा विजन साफ है। वो हमारा एक्चुअली मीटिंग शाम को है। इस पर राहुल जोर से हंसे। बगल में खड़े एक अन्य सांसद ने कहा कि भैया, ये पार्लियामेंट को छोड़ देना। राहुल ने पूछा- आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। मुखौटा पहने सांसदों ने कहा कि हम दोनों सब मिलकर करेंगे।

- सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, 70 सांसदों ने किये हस्ताक्षर- संसद के शीलकालीन सत्र में जहां एक ओर देश के अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, वहीं राज्यसभा में सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो कि इसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी 50 हस्ताक्षरों की सीमा से अधिक है।

आईआरसीटीसी वेबसाइट में दिक्कत, 24 घंटे नया अकाउंट नहीं बनेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईआरसीटीसी ने बताया है कि सोमवार 4 बजे से आज यानी 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक आईआरसीटीसी में नया रजिस्ट्रेशन, लॉग इन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने बताया है कि आज शाम 4 बजे से आज यानी 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक नया रजिस्ट्रेशन, लॉग इन पासवर्ड में बदलाव और प्रोफाइल पासवर्ड को अपडेट नहीं कर पाएंगे।आईआरसीटीसी ने इसका कारण मेंटेनेंस को बताया है।

हिमाचल में जमकर बर्फबारी, 14 दिसंबर से उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने के आसार

जम्मू-कश्मीर में 9 जगह पारा माइनस में, जोजिला में -20 डिग्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के कई हिस्सों में सामान्य ठंड के बीच जम्मू-कश्मीर में कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया। सोमवार को जोजिला (कारगिल) में टेम्परेचर -20 डिग्री, लेह में -12.8 डिग्री और गुलमर्ग में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम का पारा -6.8 डिग्री, पुलवामा -6.7 डिग्री, शोपियां -7.5 डिग्री, श्रीनगर -3.3 डिग्री, सोनमर्ग और अनंतनाग में -7.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

म.प्र.,राजस्थान,उत्तरप्रदेश में चलेगी शीतलर- मध्य प्रदेश में आज से तेज ठंड शुरू होगी, पारा 2-3 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने मंगलवार से राजस्थान में सर्दी और तेज होने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में 50 शहरों में कोहरा, शीतलहर शुरू, अलाव जलाने की व्यवस्था कर रखी है। प्रदेश में कोहरे के साथ अब शीतलहर भी शुरू हो गई है। इससे गलन भी बढ़ गई है और लोग अलावा का सहारा ले रहे हैं। वहीं, 50 जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है।

मां के सामने बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम

पाइप से पहुंचा रहे ऑक्सीजन; खेत में खुला पड़ा था 160 फीट गहरा ट्यूबवेल

दौसा (एजेंसी)। दौसा में घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोरवेल के पास में 7 जेसीबी से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। जयपुर से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक डीसी बैरवा भी मौके पर पहुंचे। हादसा पापड़दा थाना इलाके के कालीखाड़ गांव में हुआ।

चाय पत्ती की जगह मिला दिया कीटनाशक

जहरीली चाय ने ली एक ही परिवार के तीन लोगों की जान

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में एक परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जांच के बाद पता चला कि उनकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। घटना रविवार की है। दरअसल, बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत उस वक्त हो गई, जब उन्होंने चाय पी। बताया जा रहा है कि कीटनाशक युक्त चाय पीने से सभी की मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि यह घटना रविवार को हुई, जब परिवार के एक सदस्य ने चाय की पत्ती समझकर उसमें कीटनाशक मिला दिया।

● बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद! ममता के विधायक ने कहा-

मैं दूंगा एक करोड़ रुपये

कोलकाता (एजेंसी)। अपने बड़बोले बोल के कारण सुर्खियों और पार्टी की ओर ही अक्सर ही शोकॉज होते रहने वाले तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है। 75 प्रतिशत से अधिक

मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए लिए एक करोड़ रुपये दान भी देंगे। उन्होंने यह भी दावा कि छह दिसंबर 2025 से पहले ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। सोमवार को तृणमूल विधायक युमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में 34 प्रतिशत मुसलमान हैं। उनकी जो भावना है और जो बंगाल में सिर ऊंचा कर जीने की तमन्ना है, जो अधिकार हैं, उसके लिए मैं यहां से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी पनाह

तुर्किये 6 महीने पहले से जानता था विद्रोही तख्तापलट करेंगे, भारत बोला- हालात पर हमारी नजर

दमिश्क (एजेंसी)। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल–असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजीतिक शरण दी है। जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है।

जर्मनी का नागरिक रहा तेलंगाना में 20 साल विधायक

अब भरेंगे लाखों का जुर्माना, ऐसे खुली पोल

तेलंगाना में केसीआर की पार्टी के सामने बड़ी शर्मिंदगी

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बीआरएस के पूर्व विधायक डॉ. रमेश चेन्नामनेनी को जर्मन नागरिक माना। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व बीआरएस नेता चेन्नामनेनी रमेश एक जर्मन नागरिक हैं और उन्होंने वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पेश किया।

हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना- हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि रमेश जर्मन दूतावास से यह पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहे कि वह अब उस देश के नागरिक नहीं हैं। बीआरएस के पूर्व विधायक को 30 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। जिसमें से 25 लाख रुपये श्रीनिवास को देने होंगे।

जिनके खिलाफ रमेश नवंबर 2023 का चुनाव हार गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जश्न मनाने वाले पोस्ट में श्रीनिवास ने कहा कि पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश जर्मन नागरिक के रूप में झूठे दस्तावेजों के साथ विधायक चुने। अब उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना। 2020 में केंद्र ने तेलंगाना हाईकोर्ट को सूचित किया था कि रमेश के पास जर्मन पासपोर्ट है जो 2023 तक वैध है।

एक ही सीट से चार बार जीते

रमेश चेन्नामनेनी ने इससे पहले वेमुलावाड़ा सीट पर चार बार जीत हासिल की थी। 2009 में तेलुगु देशम पार्टी के हिस्से के रूप में और फिर 2010 से 2018 तक तीन बार चुनाव जीता। जिसमें पार्टी बदलने के बाद उपचुनाव भी शामिल है। भारतीय कानून के अनुसार गैर–भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या मतदान नहीं कर सकते हैं। इससे पहले 2013 में तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी कारण से उपचुनाव में उनकी जीत को रद्द कर दिया था। इसके बाद रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रोक लगाने का प्रयास किया। लेकिन रोक प्रभावी रहने के दौरान उन्होंने 2014 और 2018 के चुनाव लड़े और जीते।

NEET Pre PG काउंसिलिंग-2024 की प्रक्रिया रद्द

हाईकोर्ट के एनबीईएमएस को निर्देश- नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करें

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NEET Pre PG काउंसिलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 2024 की प्रक्रिया रद्द कर दी है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) को नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि इसके पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने काउंसिलिंग प्रक्रिया के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। पूरा मामला स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसमें कई इन सर्विस कैंडिडेट्स को रैंकिंग में पीछे कर दिया गया था।

स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने में नियमों का उल्लंघन-रीवा के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया था। इनकी ओर से वकील आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाता है।

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन काउंसिलिंग 2024 के

लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की। इससे याचिकाकर्ता की रैंकिंग प्रभावित हुई और वह राज्य की मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आए गए। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टेट मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। सैकड़ों छात्र इससे प्रभावित हैं।

अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया-कोर्ट ने नई लिस्ट बनाने को कहा है। राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है। इस नई लिस्ट से फायदा यह होगा कि मेरिटोरियस बच्चों को अच्छी सीट मिलेगी।

कोर्ट ने कहा- जो छात्र इंडिया में ऊपर, स्टेट लिस्ट में नीचे कैसे-हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सिर्फ यह नहीं होता कि एक फार्मूला बना दो और यह भी नहीं देख पाएं कि जो छात्र ऑल इंडिया रैंक में 2 हजार ऊपर है, वो स्टेट लिस्ट में 200 नीचे कैसे जा सकता है। लिहाजा यह फार्मूला पूरी तरह से गलत है। हाईकोर्ट ने पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया को रद्द कर नियमानुसार इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।

संतोष चौबे के ताजा निबंध संग्रह 'कहानी का रास्ता' लोकार्पित

भोपाल। वरिष्ठ कवि-कथाकार, विश्व रंग के निदेशक एवं रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे के ताजा निबंध संग्रह 'कहानी का रास्ता' का लोकार्पण समारोह वनमाली सभागार, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित किया गया। सर्वे प्रथम अतिथियों द्वारा 'कहानी का रास्ता' पुस्तक का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण अवसर पर संतोष चौबे ने 'कहानी का रास्ता' पर विचार रखते हुए 'वनमाली जी' को स्मरण करते हुए कहा कि कहानी का रास्ता कोई सपाट रास्ता नहीं होता। वह स्मृतियों से स्मृति में, मन से मन में और समय से समय में प्रवेश कर जाने वाला रास्ता है। कभी टेढ़ा-मेढ़ा, कभी घुमावदार, कभी पहाड़ों और कन्दराओं से गुजरा और कभी मैदान में सरपट। आईसेक्ट पब्लिकेशन, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय एवं वनमाली सृजन पीठ द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रो. विनोद तिवारी, प्रख्यात आलोचक, संपादक, पक्षधर, नई दिल्ली ने कहा कि आलोचना पाठक का उन्मुखीकरण करती है। 'कहानी का रास्ता' इसी दिशा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जेएनयू के वरिष्ठ आलोचक प्रो. देवेन्द्र चौबे ने कहा कि 'कहानी का रास्ता' आलोचना के दस्तावेजीकरण की एक नायाब पुस्तक है।

यह सृजनात्मक गद्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चर्चित कथाकार एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आशुतोष ने कहा कि संतोष चौबे की यह पुस्तक बातचीत की भाषा शैली में लिखी है। उन्होंने इसे सर्वज्ञता शिक्षक की तरह नहीं अपितु पाठक की तरह लिखा है। वरिष्ठ कथाकार एवं अध्यक्ष, वनमाली सृजन पीठ, भोपाल के अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने कहा कि 'कहानी का रास्ता पुस्तक में कहानी केन्द्र में होते हुए भी साहित्य की अन्य सारी विधाओं, विषयों और उनसे जुड़े मुद्दों की बात करती है।

यह पुस्तक रचनात्मक विचारों का गुलदस्ता है।वरिष्ठ कवि एवं वनमाली सृजन पीठ, दिल्ली के अध्यक्ष लीलाधर मंडलोई ने कहा कि कहानी का सजल है यह पुस्तक। हमारे समय में जो कलाएँ हैं, उनके कलात्मक तत्वों का समावेश बहुत शिद्दत से इस पुस्तक में हुआ है। पाठक को महत्व दिया गया है। यह एक बोलतीं किताब है। इसमें कहानी की दास्तानगोई की बात है। कार्यक्रम का संचालन युवा कथाकार एवं वनमाली कथा के संपादक कुणाल सिंह किया। अतिथियों का स्वागत सुश्री ज्योति रघुवंशी, राष्ट्रीय संयोजक वनमाली सृजन पीठ ने किया।

अनिल कुमार धडवईवाले को राष्ट्रीय कर्मवीर पुरस्कार

भोपाल। मराठी पत्रकार पत्रकारिता के जनक , पहले मराठी समाचार पत्र 'दर्पण' के सर्वेसर्वा बाल शास्त्री जांभेकर की याद में उनके ही नाम से बनाई गई महाराष्ट्र के नाशिक की प्रतिष्ठित सक्रिय संस्था संस्था दर्पणकार बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार संघ उनकी की याद में हर साल मराठी पत्रकार दिन समारोहपूर्वक आयोजित करती है इस वर्ष का पत्रकार दिन समारोह आगामी 5 जनवरी 2025 को मनाया जावेगा । उक्त समारोह में प्रसार माध्यम और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देनेवाले कर्तत्ववान व्यक्ति को राष्ट्रीय कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किया जावेगा। इस अखिल भारतीय स्तर के अवार्ड हेतु महाराष्ट्र के बाहर के एकमात्र वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अनिलकुमार धडवईवाले चयन हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 80 वर्ष पुरानी संस्था मुंबई पत्रकार संघ ने धडवईवाले का अपने भवन में विशेष समारोह आयोजित करके अभिनंदन किया है ,इसके अलावा पुणे में वहां प्रेस क्लब में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के हाथों उन्हें सम्मानित किया जा चुका है ।

शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा- लोगों को दिखाने मुकदमा करने आ गए, आज दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान

पटियाला (एजेंसी)। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार-बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहां कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वहीं, किसानों की आगे की रणनीति पर किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा- 10 दिसंबर को कोई जत्था दिल्ली रवाना नहीं होगा। भारत सरकार अपने आप में कन्फ्यूज चल रही है। यह देश के हित में नहीं है।

म.प्र.सरकार ला रही जनविश्वास बिल

● अवैध नल कनेक्शन पर 5 हजार की पेनल्टी

● कोर्ट जाकर जुर्माना भरने की जरूरत नहीं, नियमों में होगा बदलाव

भोपाल (एजेंसी)। केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अब जनविश्वास कानून बनाने जा रही है। इसमें उद्योग, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कानूनों की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा समय में इन धाराओं के उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना भी कोर्ट जाकर भरना पड़ता है।

जनविश्वास कानून में कई धाराओं में सजा का प्रावधान हटाने की तैयारी है। जुर्माना

भरने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि संबंधित विभाग के कार्यपालक अधिकारी पेनल्टी लगा सकेंगे। इस कानून को लाने का मकसद ये भी है कि अदालतों पर केस का बोझ कम हो, आम लोगों को राहत मिले।

नए कानून के मसौदे पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 6 दिसंबर को अधिकारियों के साथ चर्चा की है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम और नगर पालिका की बिना इजाजत के पानी निकासी का रास्ता बदलने पर अभी 500 रुपए पेनल्टी लगती है। इसे बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया जा सकता है। वहीं, पानी की मेन पाइप लाइन से कोई अवैध तरीके से कनेक्शन लेता है तो उसे भी पेनल्टी के रूप में 5 हजार रुपए देने होंगे। अभी 500 रुपए पेनल्टी का प्रावधान है।

लोगों के सामने अच्छा बनने की बजाए अल्लाह के सामने अच्छे बनो

इस्लाहे–मुआशरा के जलसे में पंजाब के शाही इमाम का संबोधन

इंदौर। पंजाब के शाही इमाम व मजलिस अहरार इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने रविवार शाम आयोजित इस्लाहे–मुआशरा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महफ़िल लूट ली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज व सोशल मीडिया पर ख़ासे लोकप्रिय मौलाना ने बहुत प्यारे अंदाज़ में नसीहतें कीं। दो घंटे से कुछ ज़्यादा के धाराप्रवाह उद्बोधन में उन्होंने लोगों को बार–बार झंझोड़ा, गुदगुदाया, कभी भावुक किया तो सवाल पूछ कर उनकी दिलचस्पी आज़माते भी रहे। पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (सल्ल) के जीवन से मानव प्रेम, सेवाभाव, दया, करूणा, दानवीरता आदि की मिसालें पेश करते हुए उन्होंने इंसानी रिश्तों की अहमियत समझाई। कमज़ोरों की निस्वार्थ मदद पर उभारते हुए इस ओजस्वी वक्ता ने उस ग़ुलाम की बात सुनाई, जिसे बुख़ार के बावजूद उसके स्वामी ने रात भर चक्की पीसने पर लगा दिया था। दुख में डूबा वह रोते हुए चक्की पीस रहा था। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। हज़रत मुहम्मद (सल्ल) ने देखा तो उसके पास गए। उसकी पीड़ा देख उसके लिए दूध व खजूर लाए और उसे सुला कर आटा ख़ुद पीसने लगे।

आपसी मतभेदों, गुटबंदी का उल्लेख करते हुए मौलाना उस्मान बोले कि ऐसे दयालु, कृपावान नबी सल्ल. के बारे में मतभेद रखना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। इमाम अबु हनीफ़ा से लेकर शाह वली उल्लाह तक एक हज़ार साल के दौरान तो नबी सल्ल. के बारे में बहस नहीं हुई। हम इसमें उलझ रहे हैं कि नबी सल्ल. को इल्मे–ग़ैब (भविष्य का ज्ञान) था कि नहीं था। ऐसे मामलात में एक–दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इतनी जुरअत। इसीलिए हम मार भी खा रहे हैं। नबी सल्ल. क्या हैं, यह अल्लाह जानता है। शेख़ सादी कह गए हैं कि अल्लाह के बाद बस नबी बड़े हैं। जो बंदा उस नबी सल्ल. का कलमा पढ़ता हो, वह दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देता हो। हिंदू के घर का पानी पीते वक़्त अगर घिन आने लगे तो आप मुसलमान नहीं हैं। आज कोई ग़ैर–मुस्लिम तुम से पूछ ले कि इस्लाम का पैग़ाम, मक़सद क्या है, तो बता पाओगे? उन्होंने सार प्रस्तुत किया कि रब और रसूल सल्ल. का कहा मानने के साथ लोगों को इज़्ज़त दो। ग़रीबों, कमज़ोरों की मदद करो। माता–पिता का आदर करो, बहन–बेटियों को उनका हक़ दो।

कोई बच्ची मुस्लिम हो या हिंदू, उसे गंदी निगाह से देखा तो कल क़यामत (प्रलय) के दिन तुम मुजरिम गिने जाओगे। सुबह उठ के ख़ुद को देखो, तुम में अगर कोई ठग, धोखेबाज़, व्यभिचारी, झूठा, पाखंडी है तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए। लोगों के सामने अच्छा बनने से कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह के सामने अच्छा बन के, रसूलुल्लाह सल्ल. के तरीक़ों पर चल के दिखाओ। प्रख्यात विद्वान मौलाना अश्फ़ाक़ुर्रहमान की सरपरस्ती व मौलाना तसव्वुर फ़लाही की अध्यक्षता में नौजवान उलमा–ए–किराम व दानिशवरान शहर इंदौर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उक्त दोनों विद्वानों ने अपने बोलने का समय मौलाना को भेंट कर दिया। संचालन मौलाना नौशाद ख़ान व मुफ़्ती सैफ़ुल्लाह अर्शी ने किया। हज़ारों की क्षमता वाला ग्रीन पार्क से लगा आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ था और पूरी तवज्जो पूरी यकसूई के साथ मौलाना का बयान सुनते रहे।

आम सूचना

न्यायालय नज़ूल अधिकारी, तहसील कोलार, भोपाल

क्रमांक/1277/ रीडर-2/2024
भोपाल दिनांक 02.12.2024
प्रकरण क्रमांक: 246/31-6/2024-25

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री [illegible] हरीश चंद माथुर निवासी म. न. 50, सेक्टर-1, शांति नगर, हबीबगंज, भोपाल द्वारा भू-खण्ड क्रमांक 50 स्कीम ऑफ एम.ई.ई. को-ऑपरेटिव सोसायटी शांति नगर भोपाल कुल रकबा 6000 वर्गफिट के लीज नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नजूल भूमि के लीज नामांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नज़ूल अधिकारी
तहसील कोलार, भोपाल

भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएँ और आदर्श समूचे समाज के प्रेरणास्त्रोत : मुख्यमंत्री यादव

मुख्यमंत्री ने जारी किया धनराज नाथवानी कृत राजाधिराज लव लाइफ लीला का म्यूजिकल एल्बम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण विराट व्यक्तित्व के धनी थे। भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी लीलाओं और आदर्शों के माध्यम से समूचे समाज को प्रेरणा दी है। संसार का एकमात्र सत्ता परिवर्तन ऐसा हुआ जब सत्ताधीश कंस को मारने के बाद श्रीकृष्ण सत्ताधीश बनाने के बजाय उज्जैन आकर शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा की महत्ता सिखाते हैं। वृंदावन छोड़ने के बाद भी उन्होंने गांव की संस्कृति के महत्व को दर्शाते हुए मोर मुकुट लगाना नहीं छोड़ा। पांच हजार वर्षों बाद भी कल्पनाशीलता के आधार पर जनमानस को प्रभु की लीलाओं का साक्षी बनाने का कार्य राजाधिराज लव.लाइफ.लीला नाटक का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री धनराज और श्रीमती भूमि नाथवानी सहित पूरी टीम को इस संगीतमय प्रस्तुति की लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू

स्टेडियम में धनराज नाथवानी कृत राजाधिराज लव.लाइफ.लीला के म्यूजिकल एल्बम विमोचन कार्यक्रम को संबोधित का रहे थे।

राजाधिराज लव.लाइफ.लीला भगवान श्रीकृष्ण के जीवनलीलाओं का चित्रण करता एक सुपरहिट मेगा म्यूजिकल नाटक है। इस नाट्य के गीतकार श्री प्रसून जोशी, संगीतकार सर्वश्री सचिन-जिगर, निर्माता श्रीमती भूमि नाथवानी और निर्देशक श्रीमती श्रुति शर्मा हैं। नाट्य में भारतीय शास्त्रीय और पश्चिमी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का सम्मोहक मिश्रण है, जिसमें मंच अभिनेताओं द्वारा लाइव गायन किया गया है। हवेली संगीत, राजस्थानी और गुजराती लोक, सपकरा, रास गरबा और हिंदुस्तानी अर्ध-शास्त्रीय संगीत जैसी कई शैलियों पर आधारित संगीत और कत्थक, रास गरबा, भरतनाट्यम, छऊ और कलारी जैसी नृत्यकलाओं को इस नाट्य में सम्मिलित किया गया है।

पन्ना में तीन बाघों ने 5 महिलाओं पर किया हमला, एक की मौत

4 जान बचाकर भागीं; घास काटने गई थीं

पन्ना (नप्र)। पन्ना टाइगर रिजर्व में हिनौता गेट पर तीन शावकों ने सोमवार सुबह चारा काट रही 5 महिलाओं पर हमला कर दिया। हादसे में फूला साहू (57) की हमले में मौत हो गई है। वहीं 4 महिलाएं जान बचा कर गईं। शव को प्रबंधन ने पुलिस को सौंप दिया है। बताया गया कि हिनोता गांव की 5 महिलाएं जंगल में चारा काटने गई थीं। यह कोर क्षेत्र में आता है। यहां आना-जाना और घास काटना प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में महिलाएं यहां कैसे पहुंची यह भी जांच का विषय है।

महिला पर तीन शावकों ने किया हमला

पीटीआर की फील्ड डारेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने कहा, बाघिन पी 652 के तीन शावकों हमला किया है। बाघिन और उसके तीनों शावकों की सघन निगरानी शुरू कर दी गई है। अब इन शावकों की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि जंगल के करीब न जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। घटना में टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए हैं।

पन्ना विधायक ने घटना पर जताया दु:ख

बाघ के हमले में हिनौता गांव की महिला की मौत पर पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दु:ख जताया है। उन्होंने कहा कि इस बेहद हृदय विदारक घटना के संबंध में टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक और कलेक्टर से बात की है। मृतक के परिवार को हर संभव मदद प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। विधायक निधि से भी मृतक के परिवार को सहायता प्रदान करूंगा।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर रेप का केस

विदिशा में भतीजी बोली-4 साल से धमकाकर दुष्कर्म कर रहा; घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

विदिशा (नप्र)। विदिशा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी खड़ेर पर रेप का आरोप लगा है। 23 वर्षीय पीड़िता रिश्ते में सोलंकी की भतीजी लगती है। उसकी शिकायत पर नटेरन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस की टीमें फरार सोलंकी के ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। वहीं, सोलंकी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जादौन को सोमवार सुबह अपना इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है।

पीड़िता का कहना है कि सोलंकी करीब 4 साल से लगातार उसके साथ रेप कर रहा है। उसने धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को भी बताया तो वह युवती के माता-पिता और भाइयों का मर्डर कर देगा। हिम्मत करके उसने 5 दिसंबर को नटेरन थाने में केस दर्ज कराया। रेप के आरोपी भाजपा नेता योगेंद्र सोलंकी खड़ेर की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

परिजन का मर्डर कराने की धमकी देकर किया रेप

पीड़िता ने एफआईआर में बताया, योगेंद्र सोलंकी बासौदा में रहते हैं। खेती-बाड़ी के सिलसिले में गांव आना-जाना होता रहता है। करीब 4 साल पहले एक दिन वे हमारे घर आए। उस समय मम्मी-पापा और भाई काम से गांव से बाहर गए थे। मैं घर पर अकेली थी। उन्होंने डरा-धमकाकर मेरे साथ गलत काम किया। कहा कि किसी को बताया तो तेरे मां-बाप और भाइयों का मर्डर करा दूंगा। मैं डर गई थी। इसी कारण घरवालों को कुछ नहीं बताया।

इसके बाद योगेंद्र जब भी गांव आते तो डरा-धमकाकर रेप करते। एक बार मैं बासौदा गई थी। पता लगते ही योगेंद्र मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वहां भी रेप किया। मैं इससे तंग आ गई थी। घर पहुंची तो योगेंद्र की करतूत घरवालों को बताई।

पटवारी बोले- बच्चों को पीट कर राम का नाम बुलवाया

इसके पीछे बीजेपी-आरएसएस, रतलाम मामले में इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में चर्चा की मांग रखी

भोपाल (नप्र)। रतलाम में तीन बच्चों की पिटाई कर धार्मिक नारे लगवाने पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, इसके पीछे दोषी बीजेपी और आरएसएस है। इन्होंने क्रूरता से धर्म का प्रचार करने की मानसिकता बनवा दी है। मैं सहिष्णुता से प्रचार करने को मानता हूं, यह हिंदू धर्म की फिलॉसफी है।

पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा, सामने आए वीडियो में तीन नाबालिग बच्चों को मार-मार कर कह रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलो। भगवान राम का नाम लेने के लिए भगवान ने भी किसी को यह नहीं कहा कि यह जोर-जबरदस्ती से हो, तो फिर यह करवाने वाले हैं कौन, सोच कौन सी है, विचार कौन सा है? उधर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी रतलाम मामले में राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर दी है। रतलाम में तीन बच्चों की पिटाई का वीडियो गुरुवार, 5 दिसंबर को सामने आया था। रात में मुस्लिम समाज ने शहर के माणकचौक थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की थी। वीडियो में 6, 9 और 11 साल के तीन बच्चों के साथ मारपीट की गई थी। आरोपी बच्चों को चप्पल से मारते नजर आ रहा है। उनसे धार्मिक नारे भी लगवाए। पकड़े जाने पर आरोपी 16 साल का नाबालिग निकला।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री सारंग ने की वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की समीक्षा

वाटर स्पोर्ट्स को प्रोमोट करने प्रोग्राम बनाएं: मंत्री सारंग

लेक व्यू पर सप्ताह में एक दिन वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हो

भोपाल (नप्र)। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के प्रति युवाओं और नागरिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिन लेक व्यू पर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का प्रदर्शन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक इवेंट प्रोग्राम भी बनाएं, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को पूरा शहर देखे। इसमें नगर निगम और पर्यटन विभाग सहित अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाये। मंत्री श्री सारंग सोमवार को वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

खिलाड़ियों की डाक्यूमेंट प्रोफाइल हो तैयार- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अकादमी के खिलाड़ियों की डायरी तैयार की जाये, इस डाक्यूमेंट प्रोफाइल में उसका विवरण सहित खेल में प्रदर्शन और अचीवमेंट दर्ज हो। साथ ही फिजीकल एक्टिविटी का समावेश भी हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपेक्षाएं एवं अनुदान के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाये।

खेल से मिलता है अनुशासन, संस्कार और कॅरियर

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पालकों को भी खेल के प्रति जागरूक करने के प्रयास किया जाना चाहिए। खेल से युवाओं को अनुशासन, संस्कार और कॅरियर मिलता है। इवेन्ट प्रोग्राम से बच्चों और युवाओं को खेल की गतिविधियां देखकर उनके प्रति आकर्षण और खेल की भावना जागृत होगी। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में एलईडी के माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन करवाने को भी कहा।

खिलाड़ियों की सफलता की कहानियां

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सफलता की कहानियां भी तैयार की जाये। उसका सोशल मीडिया, प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रदर्शन हो इससे युवा खेल के प्रति आकर्षित होंगे और टेलेंट सर्च करने में आसानी होगी।

स्कूली बच्चों में अकादमी के प्रति आकर्षित करने के प्रयास हों

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग और हॉकी में अपार संभावनाएं है। इस दिशा में भरकस प्रयास किये जाने चाहिए। स्कूली बच्चों को अकादमी में आकर्षित करने के लिये इसकी जानकारी उन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिये विभिन्न तरह के प्रोग्राम के जरिए उन्हें अवगत करवाना होगा।

उपकरणों की नहीं होगी कमी

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स के लिये उपकरणों की कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही कोच एवं ट्रेनर का आंकलन कर लिया जाये, उसी हिसाब से इसकी व्यवस्थाएं की जायेंगी। टेलेंट सर्च के जरिए जिनमें खेल के प्रति रूचि हो वहीं बच्चे चयनित किये जाये। इसके लिये 'खेलो-बढ़ो' अभियान का समावेश किया जाये।

खिलाड़ियों से किया संवाद

मंत्री श्री सारंग ने शुरूआत में अकादमी के बच्चों से भेंटकर उनकी समस्या और सुझाव जाने। साथ ही उनके खाने और ठहरने की व्यस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बैठक में संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एल. यादव, सहायक संचालक श्री क्षिप्रा श्रीवास्तव सहित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के कोच और ट्रेनर्स उपस्थित थे।

सुमित्रा महाजन के पोते से हाथापाई करने वाले गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर से मिले ताई समर्थक, सख्त कार्रवाई की मांग की; आज सीएम से मिलेंगे

इंदौर (नप्र)। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (ताई) के बेटे मिलिंद महाजन के शोरूम में तोड़फोड़ और उनके बेटे सिद्धार्थ महाजन से मारपीट करने वाले दर्जा प्राप्त मंत्री के भतीजे व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजाद नगर पुलिस निगम कर्मियों सहित अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेता और ताई समर्थकों में आक्रोश है। वह सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की और सख्त कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी पुलिस कमिश्नर से बात की।

इंदौर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि, 6 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनमें से किसी की भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसआईटी भी बनाया है। एक आरोपी अभी फरार है। उसे भी जल्द पकड़ लेंगे।

पुलिस कमिश्नर से मिले ताई समर्थक- पुलिस कमिश्नर से ताई समर्थक मिलने पहुंचे। इसमें एआईएमपी के अध्यक्ष योगेश मेहता, ट्रांसपोर्ट डीलर एसोसिएशन के विशाल पमनानी, पार्षद प्रशांत बड़वे, पार्षद गजानंद गावड़े, पार्षद सुरेश टाकलकर, पार्षद संगीता महेश जोशी, अशोक डग्गा, रिंकू भाटिया, राकेश अग्रवाल, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के राजेन्द्र वासु, पार्षद कंचन गिदवानी सहित 35 एसोशिएसन के लोग आए हैं।पुलिस कमिश्नर से मिलने 35 एसोशिएसन के लोग पहुंचे हैं।

कार सर्विसिंग के बिल को लेकर हुआ था विवाद- ताई के बेटे मिलिंद का नेमावर रोड पर शोरूम व सर्विस सेंटर है। आरोपी सौरभ करोसिया ने शुक्रवार देर शाम अपने साथियों साथ सर्विसिंग के बिल पर विवाद के बाद तोड़फोड़ की थी। सौरभ राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा नेता प्रताप करोसिया के भाई जितेंद्र करोसिया का बेटा है। आरोपियों ने ताई के पोते सिद्धार्थ और मैनेजर भूषण दीक्षित के साथ मारपीट भी की थी।

15 आईएएस अफसरों के तबादले

सीएम सचिवालय के बाद अब राजभवन में भी एसीएस की पोस्टिंग

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रविवार रात को इसका आदेश जारी हुआ है। जिसमें लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को हटाकर उन्हें राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। यह पहली बार हुआ है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में डॉ. राजेश राजौरा की पदस्थापना 8 महीने पहले की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव स्तर के अधिकारी और रीवा में पदस्थ अपर आयुक्त अरुण परमार की पोस्टिंग की गई है। परमार इसके पहले भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ रह चुके हैं।

16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले किए गए तबादले में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी नीरज मंडलोई और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा अनुपम राजन को सौंपा गया है।

सेलवेंद्रन से लिया आईजी पंजीयन का चार्ज- आदेश में आईजी पंजीयन की लंबे समय से जिम्मेदारी निभा रहे एम सेलवेंद्रन को इस काम से मुक्त किया गया है। उनके स्थान पर अपर सचिव कार्मिक अमित तोमर को आईजी पंजीयन और रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। वे अतिरिक्त प्रभार के रूप में जीएडी के अपर सचिव कार्मिक का भी काम देखते रहेंगे। उधर, सेलवेंद्रन के पास आईजी पंजीयन का प्रभार सौंपने के बाद सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग तथा सचिव कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार बना रहेगा। सचिव कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सेलवेंद्रन के पास होगा।

छोटे सिंह को संचालक पंचायत राज बनाया- संचालक पंचायत राज और सीईओ ग्रामीण आजीविका मिशन के पद से मनोज पुष्प को हटाए जाने के बाद इस पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इस पद पर छोटे सिंह अपर आयुक्त राजस्व ग्वालियर संभाग पदस्थ किए गए हैं। वहीं लंबे समय से राजस्व विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे दिनेश कुमार मौर्य को ओएसडी सह कंट्रोलर खाद्य और औषधि प्रशासन पदस्थ किया गया है। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर मयंक अग्रवाल को एमडी पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉरपोरेशन पदस्थ किया गया है।

मुकेश चंद्र गुप्ता बने सचिव मानव अधिकार- प्रमुख सचिव राज्यपाल मुकेश चंद्र गुप्ता को हटाकर सचिव मानव अधिकार आयोग बनाया गया है। सचिव स्तर के पद पर शासन ने प्रमुख सचिव की पोस्टिंग की है। इसके अलावा इंदौर में पदस्थ अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर रजनी सिंह को ओएसडी सह आयुक्त श्रम विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। रजनी के पास एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

एसएएस अफसर राकेश कुशरे को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा- वहीं, एक अन्य आदेश में एसएएस अफसर राकेश कुशरे को मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर उप सचिव पदस्थ किया है। इससे पहले वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव के पद पर पदस्थ थे। उनके पास कर्मचारी चयन मंडल के अपर संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी है।

भोपाल में डीजे बजाने से रोकने पर युवक की हत्या

4 दिन का बेटा सो नहीं पा रहा था; बंद करने का कहा तो आरोपियों ने गला रेता

भोपाल (नप्र)। भोपाल में तीन बदमाशों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। युवक के यहां चार दिन पहले ही बेटा पैदा हुआ है। आरोपी रविवार देर रात शराब के नशे में तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। शोर के चलते युवक का बेटा सो नहीं पा रहा था। वह आरोपियों से डीजे बंद करने के लिए गया था।

घटना रविवार रात 1.30 बजे अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की 84 एकड़ झुग्गी बस्ती की है। आरोपियों ने युवक से पहले मारपीट की। दो लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़े। तीसरे ने गला रेता और हाथ की कलाई की नस काट दी। युवक कुछ दूर तक भागा और बेसुध होकर गिर गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने आरोपियों से डीजे बंद करने को कहा था। जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी।

प्रत्यक्षदर्शी ने कहा-चाकू से गला रेत दिया- प्रत्यक्षदर्शी शिवकांत कुशवाह के मुताबिक प्रहलाद कुशवाह, राजू और प्रदीप अपनी झुग्गी में तेज आवाज में गाने बजा रहे थे। शराब के नशे में शोर भी मचा रहे थे। पड़ोस में रहने वाले मनोज चोरे (30) पिता विश्वनाथ चोरे ने आपत्ति ली। मनोज जब डीजे बंद करने के लिए कहने गया तो तीनों आरोपी विवाद कर मारपीट करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रहलाद ने चाकू निकालकर मनोज का गला रेत दिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग निकले।

खून से लथपथ युवक दौड़ा, बेसुध होकर गिरा- शिवकांत ने बताया कि घायल हालत में मनोज अपनी झुग्गी की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में ही बेसुध होकर गिर गया। शोर सुनकर परिजन और पड़ोसी बाहर निकले। इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। इसी बीच परिजन और पड़ोसी मनोज को हमीदिया अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

8 महीने पहले मोहल्ले में रहने आया था आरोपी- मनोज के जीजा राकेश कुशवाह का कहना है कि फौरन सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर तक नहीं आई। बाद में हम ऑटो से थाने पहुंचे और पुलिस को साथ लेकर घटना स्थल पर लौटे। तब तक आरोपी भाग चुके थे। मुख्य आरोपी प्रहलाद कुशवाह 8 महीने पहले ही मोहल्ले में रहने आया था। देर रात पुलिस ने प्रदीप और राजू को हिरासत में ले लिया। प्रहलाद की तलाश की जा रही है।

4 दिन पहले ही पैदा हुआ बेटा, 1 बेटा दो साल का- मनोज मजदूरी करता था। उसकी 4 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके दो लड़के हैं। बड़ा बेटा दो साल का है, छोटे ने 4 दिन पहले ही जन्म लिया है। घटना के बाद से पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

संपादकीय

असद का पतन, रूस को झटका

सीरिया में जिस आसानी से 24 सालों से तानाशाही तरीके से राज कर रहे बशर अल असद सरकार का पतन हुआ है और वहां विद्रोही ने सत्ता कब्जा ली है, उसके मध्यपूर्व में दूरगामी परिणाम होंगे। यह घटनाक्रम असद को पनाह देने वाले रूस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इससे मध्यपूर्व में एक बड़ी वैश्विक शक्ति बने रहने की उसकी हसरतों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बशर पिछले एक दशक से रूसी सैन्य शक्ति के बूते पर ही सत्ता पर काबिज रहने में कामयाब रहे थे। साथ ही बशर को अब तक समर्थन दे रहे ईरान के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि आखिरी वक्त में उसने भी असद को मदद देने से हाथ खींच लिए थे। असद ने राजधानी दमिश्क से भागकर अब रूस की राजधानी मास्को में शरण ले ली है। असद को राजनीतिक शरण देने के बाद रूस ने अमेरिका पर तंज किया है कि हम मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। सीरिया में हालात तो पहले से ही ठीक नहीं थे, लेकिन लंबे समय से देश पर शासन करते आ रहे असद खानदान का इतनी जल्दी पतन हो जाएगा, इसकी संभावना कम थी। लेकिन असद ने पहले ही अमेरिका और इजराइल से पंगा ले लिया था। मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए रूस ने असद की पीठ पर हाथ रखा था। वर्ष 2015 में मुसीबत में पड़े असद की मदद के लिए रूस ने हज़ारों सैनिक भेजे थे। मकसद यही था कि रूस खुद को एक ग्लोबल पॉवर के रूप में पेश करे। सोवियत दौर खत्म होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देने की यह पहली कोशिश थी। सीरिया में उसने अपने चार सैनिक अड्डे भी स्थापित किए थे। अब इन सैनिक अड्डों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है। जिस तरह से सीरिया में आम लोगों ने विद्रोहियों का स्वागत किया है, उससे लगता है कि जनता सीरिया के राष्ट्रपति के अत्याचारी शासन से त्रस्त थी और मौका तलाश रही थी कि कोई उसे मुक्ति दिलाए। यह काम विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेता जुलानी ने कर दिखाया है। शायद सत्ता का हस्तांतरण भी उन्हीं को होगा। लेकिन इसके बाद भी सीरिया में शांति स्थापित हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर कई विद्रोही गुटों का कब्जा है। असद के जाने के बाद इस सभी गुटों में पूरे देश कर कब्जे के लिए आपस में संघर्ष होना तय है। ऐसे में हालात और खराब होंगे। वहां कुर्द विद्रोहियों को अमेरिका समर्थन दे रहा है तो तुर्किए उनका दमन कर रहा है। विजेता विद्रोही गुट एचटीएस को पश्चिमी देशों का समर्थन बताया जाता है तो असद के पीछे रूस और ईरान खड़े हैं। वैसे सीरिया में 2011 में जबर्दस्त गृहयुद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस की मदद से जीत हासिल की थी। लेकिन अब वैसा होने की संभावना नहीं है। आशंका इस बात की ज्यादा है कि भविष्य में सीरिया के कई टुकड़े हो सकते हैं। मौके की नजाकत देख इजराइल ने भी सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले कर उसकी जमीन पर बफर जोन बनाने की कोशिश तेज कर दी है। कुल मिलाकर सीरिया अब वैश्विक शक्तियों की जोर आजमाइश का अखाड़ा बन चुका है। शांति तो वहां एक सपना है।

नजरिया

डॉ. आरके सिन्हा

लेखक पूर्व सांसद हैं।

कैसे बढ़े चुनावों में मतदान का प्रतिशत?

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में 65 फीसद से अधिक मतदान हुआ है, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। यह दो कारणों से उल्लेखनीय है: पहला, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है; और दूसरा, यह चुनावों में औसत राष्ट्रीय मतदान के करीब है, जो लगभग 65-66 प्रतिशत आंका गया है। लेकिन, प्रश्न यह उठता है कि क्या मतदान का यह प्रतिशत क्या किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं! तो फिर किया क्या जाये! पर यह तो पूरे तो पूरे देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों को यह सोचना ही होगा कि चुनावों में मतदान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह गंभीर मसला है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि महाराष्ट्र विधान सभा के लिए हुए चुनाव में 65 फीसद से अधिक मतदान हुआ है, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। यह दो कारणों से उल्लेखनीय है: पहला, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है; और दूसरा, यह चुनावों में औसत राष्ट्रीय मतदान के करीब है, जो लगभग 65-66त आंका गया है। महाराष्ट्र के आंकड़ों पर इसलिए गौर किया जाता है क्योंकि राज्य में देश की सबसे बड़ी शहरी आबादी है, और ऐतिहासिक रूप से यह शहरों और कस्बों में कम मतदान के कारण औसत राष्ट्रीय मतदान से पीछे रहा है।

महाराष्ट्र और झारखंड विधान सभाओं के लिए हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। अब दोनों राज्यों में नई सरकारों का गठन भी हो गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है।

महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में 65 फीसद से अधिक मतदान हुआ है, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। यह दो कारणों से उल्लेखनीय है: पहला, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है; और दूसरा, यह चुनावों में औसत राष्ट्रीय मतदान के करीब है, जो लगभग 65-66 प्रतिशत आंका गया है।

लेकिन, प्रश्न यह उठता है कि क्या मतदान का यह प्रतिशत क्या किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं! तो फिर किया क्या जाये! पर यह तो पूरे तो पूरे देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों को यह सोचना ही होगा कि चुनावों में मतदान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह गंभीर मसला है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 65 फीसद से अधिक मतदान हुआ है, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। यह दो कारणों से उल्लेखनीय है: पहला, यह 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े से लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है; और दूसरा, यह चुनावों में औसत राष्ट्रीय मतदान के करीब है, जो लगभग 65-66 प्रतिशत आंका गया है। महाराष्ट्र के आंकड़ों पर इसलिए गौर किया जाता है क्योंकि राज्य में देश की सबसे बड़ी शहरी आबादी है, और ऐतिहासिक रूप से यह शहरों और कस्बों में कम मतदान के कारण औसत राष्ट्रीय मतदान से पीछे रहा है।

हालांकि, महाराष्ट्र के आंकड़े का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 76.25 प्रतिशत का उच्च मतदान दर्ज किया गया, उसके बाद गढ़चिरौली का स्थान है, जो माओवादियों की गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहता है, जहाँ 73.68 प्रतिशत मतदान हुआ है, जबकि मुंबई शहर जिले में 52.07 प्रतिशत का कम मतदान हुआ। पुणे, ठाणे और मुंबई उपनगरीय जैसे अन्य शहरी जिलों में भी इसी तरह के आंकड़े दर्ज किए गए हैं।

हालांकि, सकारात्मक पहलू यह है कि पूरे राज्य में मतदान में समग्र सुधार हुआ है। इस बदलाव का श्रेय, हालांकि अपेक्षाकृत धीमा और क्रमिक है, इसका मुख्य रूप से श्रेय भारत के वर्तमान चुनाव आयोग को जाता है। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग इस बार काफी सक्रिय था। इसके अभियान में, सोशल मीडिया सहित, स्थानीय हस्तियों - क्रिकेटरों से लेकर फिल्म सितारों तक को भी शामिल किया गया है, और इसमें ऊँची इमारतों और आवासीय सोसायटियों में मतदान केंद्र स्थापित करना और कतार में लगने के समय को कम करने के लिए टोकन प्रणाली शामिल है। राजनीतिक दलों के उच्च-वोल्टेज अभियानों ने भी मतदाता भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। महाराष्ट्र में बेहतर मतदान भारतीय लोकतंत्र के लिए आश्वस्त करने वाला है।

हालांकि यह मानना होगा कि देश के शहरी इलाकों में मतदान कमोबेश कम ही रहता है।शिमला से सूरत तक शहरी मतदाता की उदासीनता लगातार बनी हुई है। यह रुझान नया नहीं है। चुनावों के पहले तीन दशकों में, शहरी मतदाताओं की भागीदारी काफी बेहतर रहती थी। 1980 के दशक से शहरी और ग्रामीण मतदान के बीच का अंतर बढ़ गया है। शहरी उदासीनता को समझना होगा। शहरी भारत का जीडीपी में 60 प्रतिशत और करों में बहुत बड़ा हिस्सा है। पर हमारे यहां के शहरों की हालत लगातार खराब हो रही है। आजकल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जिस तरह का हो गया है, उसने आम लोगों का जीना दूधर कर दिया है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। यह तो राजधानी की हालत है। गुजरे कुछ सालों के दौरान दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, बैंगलुरू जैसे देश के अति अहम महानगर बारिश से जलमग्न होते रहे। इनमें जिंदगी कई दिनों तक थमी रही। सड़कों पर जलभराव के कारण जाम लग गए, रेल सेवा प्रभावित हुई, घरों में पानी जाता रहा, स्कूल-कॉलेज बंद हो गए। देश के इन खासमखास शहरों की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर गई। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। यह स्थिति हर साल होती है, योजनाएं बनती हैं ताकि बारिश के बाद होने वाली अव्यवस्था और अराजकता की पुनरावृत्ति ना हो। पर योजनाएं फाइलों में गुम हो जाती हैं।

यह समझना होगा कि शहरी भारत, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देश का लगभग सारा सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) शहरों में ही सिमटा है। जनगणना के आंकड़ों को माने तो देश की 31 फीसद आबादी शहरों में रहती है। हालांकि गैर-सरकारी आंकड़ें शहरी आबादी कहीं अधिक होने का दावा करते हैं। इन शहरों में रोजगार के अवसर हैं। सारे देश के नौजवानों के सपने इन्हीं शहरों में पहुंचकर साकार होते हैं। पर नीति निर्धारकों के फोकस से कहीं दूर बसते हैं शहर।

जाहिर है, इस कारण से मतदाता निराश होने लगता है अपने जनप्रतिनिधियों से। उसे लगता है कि जब उसके नेता निकम्मे होंगे तो वह वोट क्यों करे। मतदाताओं को नेता बार-बार निराश करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि अगर देश में मतदान केन्द्रों की तरफ फिर से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर लाना है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की ही नहीं है। उन्हें भी जनता से सीधा संपर्क बनाकर रखना होगा। उन्हें भी जनता के मसलों को लेकर संवेदनशील बनना होगा।

आपको याद ही होगा पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त लगभग सारे में देश सूरज देवता आग उगल रहे थे। फिर भी मतदाता मतदान करने के लिए घरों से निकल रहे थे। मतदान वाले दिन कई जगहों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। लू भी चल रही है। इतने कठोर मौसम में चुनाव प्रचार करना और फिर मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़ा होना सामान्य बात नहीं थी। इतने खराब मौसम में भी देश के लाखों-करोड़ों मतदाता घरों से निकलकर वोट तो दे ही रहे थे। यह सुखद भी है और हमारे मजबूत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी है। आखिर देश के जनमानस को पता है कि उनके वोट से ही देश की तकदीर लिखी जाएगी। इसलिए ही लोग वोट देकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करते हैं।

पहले से ही सक्रिय, चुनाव आयोग को अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, मतदान केंद्रों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना होगा। इसमें पर्याप्त पार्किंग और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र जैसे सुधार शामिल हो सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर में ही वोट देने की सुविधा दी जा सकती है। फिलहाल तो दिव्यांग जनों को मतदान केन्द्रों में काफी कष्ट होता है। इस तरफ गंभीरता से सोचना होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंचायत, नगरपालिका, विधान सभा और लोकसभा चुनावों में मतदान को बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की ही नहीं है। इस दिशा में कई स्तरों पर काम करना जरूरी है।

सरोकार

ऋतुराज बुड़ावनवाला

लेखक पत्रकार हैं।

एक्सप्रेस-वे बना नहीं, गांव सफर करने लगा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मोटरसाइकिल, स्कूटी, ट्रैक्टर और ऑटो चलाने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पहिया वाहन एक्सप्रेस-वे पर दौड़ रहे हैं। बीते डेढ़ वर्षों में दोपहिया वाहनों की चोपहियां वाहनों के साथ हुई भिड़ंत में अनेकों लोगों की मौत हो गई। आए दिन दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी हैं। हर-दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबर मिलती रहती हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का मध्यप्रदेश खंड सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ।

एक्सप्रेस-वे पर अनधिकृत यातायात चल रहा है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक्सप्रेस वे की साईड़ो को अपनी सुविधानुसार काटकर दो पहिया वाहनों से आवाजाही की जा रही है। यहीं नहीं, ये लोग अपने दोपहिया वाहनों पर सवार होकर विपरीत दिशा में भी यात्रा करने से परहेज नहीं करते। गुजरात की और से मध्यप्रदेश के मेघनगर से लगी अनास नदी से मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से होकर गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर खासतौर पर रावटी, शिवगढ़, खवासा जैसे थाना क्षेत्रों में अज्ञात लोगों द्वारा आए दिन वाहनों के ऊपर पत्थर बरसाएं जा रहें हैं। जिससे एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने वाले यात्रियों में भय गहराया हुआ हैं। झाबुआ, थांदला, रतलाम, सैलाना, धामनोद,नामली, जावरा, खाचरौद जैसे क्षेत्र के जानकार लोग तो शाम 5 बजे के बाद एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करने से परहेज करते हैं।

सुवासरा के फोटोग्राफर एवं साहित्यकार बंसीलाल परमार ने बताया कि हाईवे के आसपास के लोगों के लिए हाईवे की ओर देखना वैसा ही है जैसे आसमान में हवाई जहाज को गुजरते हुए देखना। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव के पास से हाईवे गुजरने वाला है, तो उनकी आंखों में विकास का सपना तैरने लगता है। लेकिन हाईवे जब निकला तो अपने साथ कई समस्याएं लाया। कई किसानों के खेत अधिग्रहण में चले गए। मुआवजा चाहे कितना ही मिला,जमीन के एवज में यदि वह जमीन खरीद पाया तो ठीक, नहीं तो उचित निवेश न होने पर सारा धन खर्च कर मजदूर बन जाता है। किसान व्यापारी नही होता। वह लाखों को करोड़ों में नहीं बदल सकता। इस मार्ग पर थादंला, सैलाना, तथा झाबुआ जिले में किसानों को खेत में जाने का रास्ता नहीं दिया गया, जिससे वे परेशान है। बहुत से लोगों की जमीन का कुछ भाग सड़क के इधर और कुछ भाग उधर रह गया, जिससे मिलों चक्कर काट कर ही वह अपने मवेशियों के साथ खेतों में पहुंच रहा है, जिससे काफी समय ,धन और ऊर्जा खर्च होती हैं।

सरकार का लक्ष्य चंद पूंजीपतियों को पोषित करना है। लोग सोचते कि हाईवे बनने से रोजगार बढ़ेगा, यह दिवास्वप्न है ! हाईवे पर जो होटल आवंटित होगी, वहां कई गुना कीमत पर खाद्य पदार्थ बिकेगे। सड़कों के किनारे के गांवों के ढाबे, चाय की दुकानें बंद हो जाएगी, जिससे अनेकों के समक्ष रोजगार के लाले पड़ जाएंगे। रतलाम के तत्कालीन एसपी राहुल लोढ़ा ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रतलाम के पास बढ़ती पथराव की घटनाओं के मद्देनजर यहां पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए गत जुलाई माह में अलग-अलग पांच स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। उनके तबादले के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा है। थानों में स्टाफ की कमी के चलते पुलिस पर्याप्त पेट्रोलिंग भी नहीं की जा रही। उल्लेखनीय है कि दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस-वे के मध्यप्रदेश के 224 किमी के हिस्से में करीब डेढ़ साल से आवागमन शुरू हो गया है।

मंदसौर, रतलाम व झाबुआ जिले के लिए वाहन प्रतिदिन गुजर रहे है। इस मार्ग पर वाहनों व यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। पिछले डेढ़ साल में अनेक बार वाहनों पर पथराव किए गए। बदमाशों द्वारा किए पथराव में

अनेक चोपहियां वाहनों को नुकसान हुआ। गत वर्षों में रावटी ब्रिज व शिवगढ़ के ग्राम बायडी तथा झाबुआ जिले से लगे क्षेत्रों में अनेकों बार पथराव की घटनाएं हो चुकी है। एक फरवरी 2024 को पूर्व विधायक दिलीप मकवाना के स्कॉर्पियो वाहन पर रावटी के समीप पथराव किया गया था, जिससे वे बाल-बच गये थे। शिवगढ़ पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन पुलिस पथराव करने वालों का पता नहीं लगा पाई।

इसका मतलब है कि अगर आप 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 100 रुपये का टोल देना होगा। अगर आप बस या ट्रक से यात्रा करते हैं तो टोल दरें और भी अधिक होती हैं। इन वाहनों के लिए टोल दर प्रति किलोमीटर 10 रुपये होती है। यानी 50 किलोमीटर की यात्रा पर आपको 500 रुपये का टोल देना होगा। भारी कमर्शियल वाहन के लिए टोल दरें प्रति किलोमीटर 12 रुपये होती हैं जबकि बड़े 3 एक्सएल वाहन के लिए यह दर 16 रुपये प्रति किलोमीटर तक होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो भारी कमर्शियल वाहन के लिए आपको 1200 रुपये और बड़े 3 एक्सएल वाहन के लिए 1600 रुपये का टोल देना होता हैं। हाईवे पर चढ़ने और उतरने की जगह पर इंटरचेंज टोल लगाए गए हैं। हर 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट के लिए गेट हैं जहां टोल ऑटोमेटिक कट जाता हैं। पूरे एक्सप्रेस-वे पर 30 लेन टोल प्लाजा बनाये गये हैं। एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम 120 की स्पीड से वाहन चलते हैं। एक्सप्रेस वे की विशेषता यह है कि कहीं भी टोल गेट नहीं लगे है। सफर के दौरान यात्रियों को बार-बार टोल के लिए रुकना नहीं पड़ता।

एक्सप्रेस-वे अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लेंस है। इस एक्सप्रेस-वे कंट्रोल हाईवे पर रात दिन मॉनिटरिंग होती। हैं। हर 1 किलोमीटर पर 500 मीटर तक की रेंज वाले हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। हर 5 किलोमीटर पर स्पीड मॉनिटर हो रही हैं। स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है तो हाईवे पेट्रोलिंग टीम के पास तत्काल ओवर स्पीडिंग वाहन का फोटो और नंबर पहुंच जाता हैं। ओवर स्पीड वाहनों पर लगे जुर्माने को भी टोल टैक्स के साथ इंटरचेंज से निकलने पर वसूल कर लिया जाता है। इसके लिए रतलाम जिले के जावरा के पास कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां स्पीड मॉनिटरिंग वाले एक्सपर्ट तैनात हैं। उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई हैं।

एक्सप्रेस वे का 244 किलोमीटर लंबा हिस्सा झाबुआ, रतलाम व मंदसौर जिले में है। रतलाम जिले में 90, झाबुआ जिले में 50.95 व मंदसौर में 102 किमी से गुजर रहा है। कई जगहों पर रेस्ट एवं सर्विस एरिया का निर्माण किया गया है, जहां पर रुककर लोग फ्रेश हो सकते हैं साथ ही आराम भी कर सकते हैं। यात्री सुविधा के लिए कार पार्किंग, फ्यूल पंप, रेस्टोरेंट, टॉयलेट के लिए भवन तो बनकर तैयार हैं, किन्तु उन्हें चालू नहीं किया गया। लंबी दूरी के यात्रियों को फ्यूल भरवाने के लिए इंटरचेंज से निकलना पड़ता है तथा खानपान की व्यवस्था नहीं होने पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्सप्रेस-वे की बाउंड्री के बाहर किनारों पर पास के ग्राम तलावड़ा के मानसिंह ने खानपान की छोटी सी दुकान खोली है, जहां पर यात्रियों की चाय-पानी की जुगाड़ हो जाती है। दारू पीने वालों और पत्थरबाजों के कारण वे दिन में ही अपनी दुकान खोलते हैं, जबकि एक्सप्रेस-वे के उस पार सांवरिया रेस्टोरेंट नामक दुकान चौबीसों घंटे खुली रहती हैं, जहां पर सुबह 6.30 बजे महिला दुकानदार चाय बनाती है।

मानवता के श्रेष्ठतम योगदान का सम्मान

नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को स्वीडन के जाने-माने वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की पुण्य स्मृति में स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित एक भव्य समारोह में नोबेल फाउंडेशन द्वारा कुछ महान् हस्तियों को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान 'नोबेल पुरस्कार' प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विश्व शांति, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है।

नोबेल पुरस्कार समाज में परिवर्तनकारी प्रभाव डालने वाले कार्यों और अनुसंधानों को मान्यता प्रदान करता है। वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार छह अलग-अलग श्रेणियों में कुल 12 व्यक्तियों तथा संगठनों को दिए गए हैं। इस वर्ष दुनिया की जिन महान् हस्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनमें शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन 'निहोन हिंडाक्यो' को परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए और परमाणु बम पीड़ितों (हिबाकुशा) की कहानियों के माध्यम से शांति के लिए काम करने हेतु प्रदान किया गया है। साहित्य में 2024 का नोबेल दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन और काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक पीड़ा और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर किया है।

2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरॉन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को संस्थानों की भूमिका पर उनके शोध के लिए दिया गया है, जिसमें दिखाया गया कि समावेशी संस्थान दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं जबकि शोषणकारी संस्थाएं इसे रोकती हैं। चिकित्सा/फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को 'माइक्रोआरएनए' की खोज के लिए प्रदान किया गया है, जिन्होंने जीन नियमन में एक नई प्रक्रिया को उजागर किया। उनकी यह खोज यह समझने में मदद करती है कि जीव कोशिकाओं में कौन से जीन सक्रिय होते हैं और क्यों? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जेफ्री हिंटन और जॉन होपफील्ड को एआई और मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले नए तरीके विकसित करने के लिए दिया गया है। इन तरीकों का उपयोग डेटा के स्वचालित विश्लेषण में होता है, जो आज की एआई प्रौद्योगिकी का आधार है।

रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, और जॉन जंपर को प्रोटीन की संरचनाओं को समझने और डिजाइन करने के लिए एआई आधारित मॉडल 'अल्फाफोल्ड-2' के विकास के लिए मिला है। इस तकनीक के कारण जीवन विज्ञान में बड़े बदलाव आए हैं। नोबेल पुरस्कारों को दुनियाभर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार 1901 से निरंतर दिए जा रहे हैं और इनकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत हुई थी। उनकी वसीयत का उद्देश्य 'मानवता के लिए महानतम लाभ प्रदान करने वाले कार्यों' को पहचानना था। नोबेल पुरस्कार विज्ञान, साहित्य और शांति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने की प्रक्रिया बेहद कठोर और पारदर्शी होती है। नोबेल समितियां स्वतंत्र रूप से अनुसंधान, समीक्षा और निर्णय लेती हैं, जिससे पुरस्कारों की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनी रहती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अपने-अपने क्षेत्रों में आदर्श बनते हैं, जो अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। इन पुरस्कारों को प्राप्त करना किसी के कार्य की उत्कृष्टता की सार्वभौमिक मान्यता है। विजेता अक्सर उन खोजों अथवा गहन प्रयासों के लिए सम्मानित होते हैं, जिनका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक होता है। उदाहरण के लिए, पेनिसिलिन की खोज से लाखों जानें बचाई गई और शांति प्रयासों ने देशों और समुदायों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद की। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम (स्वीडन) में जन्मे अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर, और आविष्कारक थे, जिन्हें डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध उद्योगपति और लेखक भी थे। अल्फ्रेड ने रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कई भाषाओं में दक्षता हासिल की थी। 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी। यह बारूद की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी विस्फोटक था। डायनामाइट ने खनन, निर्माण और इंजीनियरिंग में क्रांति ला दी थी लेकिन युद्धों में भी इसका उपयोग किया जाने लगा, जिससे अल्फ्रेड को घोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अंततः अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में डायनामाइट के आविष्कार से अर्जित हुई अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक फंड में दान करने का निर्णय लिया, जिससे नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 पेटेंट हासिल किए थे और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नोबेल फाउंडेशन को दान किया था। नोबेल पुरस्कारों के जरिये उनका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना था, जिन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ी सेवा प्रदान की। अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए भारी-भरकम धनराशि देने के लिए 27 नवम्बर 1895 को एक वसीयत लिख दी थी। 10 दिसम्बर 1896 को उनकी मृत्यु के बाद 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने शुरू हुए और इस वर्ष नोबेल पुरस्कारों को 124 वर्ष पूरे हो गए हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

लेखक व्यंग्यकार हैं

जहाँ ठोस विचार केवल धुंआ होते हैं

गाँव में एक दिन एक अनोखाी घटना घटी। गाँव के बुजुर्ग रामशंकरजी, जिन्हें लोग 'नास्तिक' के नाम से जानते थे, अपने घर के बाहर खड़े होकर उन वादियों का निरीक्षण कर रहे थे, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वे अपनी आँखों से बर्फीली हवाओं के झोंकों को निहारते हुए यही सोच रहे थे कि 'कभी ये हवाएँ मुझे भी छूने आती थीं, पर अब ये केवल उनके पास जाती हैं जिनके पास सर्दियों के लिए कंबल होता है।'

अब रामशंकरजी का मन किसी और दिशा में था। वे हर बार यह मानते थे कि आधुनिकता अब केवल उनके जैसे वृद्धों को ही परेशान करती है, जिनके पास वृद्धावस्था के सिवा और कुछ नहीं होता। वे खड़े-खड़े गाँव के उन सभी लोगों पर विचार कर रहे थे, जिन्होंने 'आधुनिकता' के नाम पर बूट और जैकेट पहन रखे थे, जबकि उनके खुद के पास केवल लाठी और बेतरतीब चप्पलें थीं।

अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, 'रामशंकरजी, आपका पोता हरिशंकर, गाँव के चुनावी रैली में गया है, उसे बहुत अच्छे से तैयार किया गया है।'

रामशंकरजी एक लम्हे को चौंके। उन्होंने अपना सिर झटकते हुए कहा, 'तो फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखता?'

तभी गाँव के सबसे सम्मानित हस्ती, पं. हरिहरनाथ जी, रामशंकरजी के पास आकर बोले, 'रामशंकरजी, आपको तो आदर्श नागरिक का उदाहरण बनना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि ये जो हरिशंकर की राजनीति में रुचि है, वह केवल दिखावे की है, या फिर उसके भीतर कुछ ठोस विचार हैं?'

रामशंकरजी ने चश्मा सही किया और मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहा, 'बिल्कुल! राजनीति के अंदर ठोस विचार तो वैसे ही होते हैं, जैसे घर के अंदर वॉर्डरोब में रखा बर्तन। बस फर्क इतना है कि बर्तन कभी काम आता है, लेकिन राजनीति में ठोस विचार केवल धुंआ उगलते हैं।'

'क्या मतलब?' हरिहरनाथ जी ने एक शंका जताई।

रामशंकरजी ने अपना चश्मा और अधिक चमकाते हुए कहा, 'मतलब यह है कि जिस चुनावी रैली में वह भाग ले रहे हैं, उसमें जीतने के बाद वह केवल अपनी जाति की कुर्सी पर बैठेंगे, और हमें जो अपना वोट उन्हें देंगे, वो कुर्सी किसी और की हो जाएगी, जो शायद सिर्फ उनका हाथ पकड़कर कहीं और चला जाएगा।'

इतने में गाँव के प्रमुख नेता, श्रीनाथ जी, जो रैली के संयोजक थे, पास आकर बोले, 'रामशंकरजी, आप भी न! हरिशंकर जैसे बच्चों की कड़ी मेहनत को क्यों नकारते हो? क्या आपके जमाने में ऐसा कुछ था?'

रामशंकरजी मुस्कुराते हुए बोले, 'क्या जमाना था! पहले हम लोग मेहनत करते थे, पर अब तो मेहनत ही राजनीति में बदल गई है। लोग अब सिर्फ किस्मत का ताला खोलते हैं और हमें बता देते हैं कि हम में कोई ताज नहीं, बस एक अदृश्य सौभाग्य ही है जो हमें पराजित होने से बचाता है।'

हरिहरनाथ जी ने चिढ़ाते हुए कहा, 'अब आप ज्यादा कहने लगे हैं। हरिशंकर अच्छा लड़का है, बस उसे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए।'

रामशंकरजी ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, 'मेहनत तो वह भी करता है, पर उसकी मेहनत केवल रैली में भाग लेने और 'वोट माँगने' तक सीमित रहती है। बाकी कहीं कोई सुधार नहीं।'

इतने में गाँव के अन्य युवक, जो हरिशंकर के समर्थक थे, आकर बोल पड़े, 'रामशंकरजी, आप न पुराने विचारों के आदमी हो गए हो! आजकल के युवा सचमुच बदलाव ला रहे हैं!'

रामशंकरजी ठहाका मारते हुए बोले, 'बदलाव? क्या बदलाव लाए हैं ये? बदलाव तो उसी गाँव में लाने का नाम है, जहाँ के पेड़-पौधे भी सजे हुए नहीं दिखते, और सड़कें तो फिर क्याज गड्ढों से भरी रहती हैं। बस, ये लोग बदलाव का नाम लेते हैं, लेकिन जो चीज़ सुधरने की जरूरत है, वो उनके मनोबल में है, न कि रोड शो में।'

सभी लोग चुप हो गए। किसी को अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और यह वही वक्त था जब रामशंकरजी को समझ में आ गया कि गाँव के लोग केवल तात्कालिक सुधार की बातें करते हैं, जबकि वास्तविक सुधार तो जड़ में होता है, जो तब दिखता है जब किसी को अपनी ग़लतियों का एहसास होता है।

कानून और न्याय: ईवीएम पर फैसला-1

ईवीएम सरल, सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने महत्वपूर्ण फैसले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बारे में आलोचना से जुड़े पाखंड के स्तर को संकेत देते हुए कहा कि हारने पर ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है और जीतने पर ठीक है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हमारी राय में ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मतपत्रों पर वापस लौटाने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ईवीएम ठीक हैं, अगर आप जीतते हैं और अगर हारते हैं तो छेड़छाड़ की जाती है। इंजीलवादी केए पॉल द्वारा दायर याचिका को खारिज करने से पहले न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने यह मौखिक टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने मतपत्रों पर लौटने के लिए न्यायिक आदेश की मांग की थी। उनका कहना था कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में मतदान अधिकारी ईवीएम और वीवीपीएटी को अपने-अपने केंद्रों पर ले गए हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वे अदालत को राजनीतिक क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अदालत में कोई राजनीति नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों की उनकी यात्राओं से पता चलता है कि दुनियाभर के लोकतंत्रों में मतपत्र प्रणाली का पालन किया जा रहा है। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि न्यायालय संविधान दिवस पर उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पैरवी करते हुए कहा कि भारत के चुनाव आयोग को कम से कम पांच वर्षों के लिए चुनावों के दौरान उपहार, धन, शराब वितरित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार समानता, कानून की उचित प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अप्रैल 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में मतपत्रों को फिर से शुरू करने से इनकार करते हुए मतदान की ईवीएम प्रणाली को बरकरार रखा था। मतपत्र प्रणाली की कमजोरी सर्वविदित और प्रलेखित है। लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं के विषाल आकार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या जहां मतदान होता है, और मतपत्रों के साथ आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हम मतपत्रों को फिर से शुरू करने का निर्देश देकर चुनावी सुधारों को पूर्ववत करेंगे। ईवीएम महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी संस्थान या प्रणाली के प्रति अंधविश्वास अनुचित संदेह पैदा करता है और प्रगति को बाधित करता है। सितंबर 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि ईवीएम को न तो हैक किया जा सकता है और न छेड़छाड़ की जा सकती है। 450 पन्नों के हलफनामे में, शीर्ष चुनाव निकाय ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरफ से स्टैंड-अलोन मशीनें हैं जिनमें एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप्स हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मतपत्रों से चुनाव की वापसी नहीं होगी। सुरक्षित और इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम अनुकूल है। न्यायालय ने ईवीएम में डाले गए मतपत्रों के शत प्रतिशत सत्यापन की प्रार्थना भी खारिज कर दी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के कामकाज में अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों द्वारा मुद्रित पर्ची के साथ उनमें डाले गए वोटों के शत प्रतिशत सत्यापन पर वैकल्पिक रूप से मतपत्रों की प्रणाली में वापसी की मांग को खारिज कर दिया। अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसलों में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम तंत्र के प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा की। खण्डपीठ ने कहा कि हमारे लिए, यह स्पष्ट है कि कड़ी जांच के साथ कई सुरक्षा उपाय और प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि उसके सामने रखे गए आंकड़े कलाकृति और छल का संकेत नहीं देते हैं।

खंडपीठ ने उम्मीदवारों को चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अधिसूचित की जाने वाली लागत के लिए एक लिखित अनुरोध पर, यदि यह पाया जाता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो रिफंड के प्रावधान है। इसके साथ ही प्रति विधानसभा खंड में पांच प्रतिशत ईवीएम की बर्न मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर प्राप्त करने का विकल्प ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद जांचा और सत्यापित किया जाता है। इसने यह भी निर्देश दिया कि 1 मई 2024 को या उसके बाद किए गए वीवीपीएटी में प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर प्रतीक लोडिंग इकाइयों (एसएलयू) को सील कर दिया जाएगा और कंटेनर में सुरक्षित किया जाएगा। एसएलयू वाले सीलबंद कंटेनर को परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उन्हें खोला जाएगा और उनकी जांच की जाएगी और ईवीएम की तरह उनसे निपटा जाएगा।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हमारी राय में, ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। मतदाता, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि और निर्वाचन आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की बारीकियों से अवगत हैं। वे धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की जांच और सुनिश्चित भी करते हैं। इसके अलावा, वीवीपीएटी प्रणाली का समावेश वोट सत्यापन के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि यह ध्यान रखना तत्काल प्रासंगिक है कि हाल के सालों में, कुछ निहित स्वार्थ वाले समूहों की एक प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो रही है, जो राष्ट्र की उपलब्धियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह उपलब्धि इसके ईमानदार कार्यबल की कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से अर्जित की गई है।

ऐसा लगता है कि हर संभव सीमा पर इस महान राष्ट्र की प्रगति को बदनाम करने, कम करने और कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के किसी भी प्रयास को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी संवैधानिक न्यायालय, चाहे यह सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों न हो, इस तरह के प्रयास को तब तक सफल होने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि इस मामले में उसकी कोई राय है। मतपत्रों की वापसी की प्रार्थना को विफल और अस्वस्थ बताते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मतपत्र प्रणाली की कमजोरी सर्वविदित और प्रलेखित है। भारतीय संदर्भ में, लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं की विशाल संख्या, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या और मतपत्रों के साथ आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हम मतपत्रों को फिर से शुरू करने का निर्देश देकर चुनावी सुधारों को पूर्व काल में ले जाने का प्रयास करेंगे।

(शेष अगले कॉलम में)

मानवाधिकार दिवस पर विशेष

मानव अधिकारों की कठिन होती डगर

चित्रा माली

स्वतंत्र टिप्पणीकार

मानवाधिकारों का अभिप्राय ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और वे व्यक्ति के ऐसे अधिकार है,जिनसे उसे किसी भी स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता है स्वयं उसके चाहने पर भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना के प्रारंभ में ही यह उल्लेखित किया गया है कि 'विश्व में स्वतंत्रता,न्याय और शांति की नींव मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गरिमा और उनके अहस्तांतरणीय तथा समान अधिकारों की स्वीकृति है। मानवाधिकारों का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें संपूर्ण मानवीय कार्य व्यापार इनके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। स्वतंत्रता,न्याय और शांति की नींव मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गरिमा और उनके अहस्तांतरणीय तथा समान अधिकारों की स्वीकृति है। मानवाधिकारों का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें संपूर्ण मानवीय कार्य व्यापार इनके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। स्वतंत्रता इनके मूल में निहित है,स्वतंत्रता के बिना अधिकारों की कल्पना भी संभव नहीं है। जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो यहां राष्ट्र की स्वतंत्रता के साथ -साथ व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात कर रहे है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना उसके अधिकारों का हनन है। जब हम मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं तो इन अधिकारों को अर्जित करने का एक लंबा संघर्ष है और इतिहास है जो हमारे अधिक मानवीय, सभ्य और विकसित होने की निशानी भी है। 1215 के मैगनाकार्टा के बाद 1679 में हैबियस कार्पस एक्ट (बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम) को पारित किया गया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया था। अमरीकन बिल ऑफ राइट्स 1776 में अमरीकी जनता ने स्वतंत्रता की मांग की और एक घोषणा पत्र जारी किया,जिसमें यह कहा गया कि 'मनुष्य जन्म से स्वतंत्रता और समानता तथा सभी अधिकारों का सक्रिय भोक्ता है और इन्ही अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारें बनाई जाती हैं'। 1789 में अमरीकी संविधान में संशोधन किया गया और दो वर्ष बाद 1791 में बिल ऑफ राइट्स को अमरीकी संविधान में जोड़ दिया गया। बिल ऑफ राइट्स में धर्म की स्वतंत्रता,भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता,अनुचित तलाशी के विरुद्ध अधिकार,निष्पक्ष न्याय व संपत्ति के अधिकार, सजा व जुर्माने से सुरक्षा का अधिकार, दासता से मुक्ति व राज्यों के द्वारा रंगभेद व जातिभेद से मुक्ति का अधिकार,वयस्क मताधिकार के अधिकार को इसमें शामिल किया गया था जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। 1789 की फ्रांस की क्रांति से तीन बीज मंत्र निकले थे स्वतंत्रता,समानता और भाईचारा जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। यह फ्रांसीसी जनता की मूलभूत स्वतंत्रताओं का घोषणा पत्र था जिसे 26 अगस्त 1789 में राष्ट्रीय असेंबली वाल्टेर ने नागरिकों के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। इस घोषणा पत्र में 17 धाराएं थी। स्वतंत्रता,समानता के अधिकार के साथ किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता है अर्थात शासन की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अतिरिक्त नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में भी मनुष्य की स्वतंत्रता को केंद्र में रखा गया है। मानवाधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण बात है कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक तंत्र में मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा औपचारिक तौर पर सिर्फ कानूनों और घोषणाओं में ही व्यक्त की जाती है या व्यवहार में और राजनीतिक संस्कृति में भी वे अभिव्यक्ति पाती हैं ? इस संदर्भ में इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अंतर्विरोधों से भरे इस समय में मानवाधिकारों के हनन की समस्या विश्वव्यापी है। भले ही वे विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र सभी राष्ट्रों में मानवाधिकारों का हनन जारी है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे संभ्रांत लोकतांत्रिक देशों में आज भी गैर - यूरोपीय मूल के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अमेरिका में पुलिस के द्वारा अल्पसंख्यकों और अश्वेतों को यातनाओं का शिकार बनाया जाता है। आस्ट्रेलिया की जेलों में सबसे अधिक मृत्यु वहां के मूल निवासियों की होती है। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में बिना मुकदमें दायर किए वर्षों से लोगों को जेल में कैद रखा गया है। राजनीतिक प्रतिवादियों को भी सींखजो के पीछे ठूस दिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुनियोजित तरीके से हत्याओं का होना सामान्य घटना है। कई देशों में कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए उनके नाखूनों में सुई चुभोई जाती है,बिजली के झटके दिए जाते हैं, आंखे फोड़ दी जाती हैं, कोड़े लगाए जाते हैं,हाथ काट दिए जाते हैं और भी कई अमानवीय यातनाएं दंडस्वरूप दी जाती है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'एमनेस्टी इंटरनेशनल','इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स', 'इंटरनेशनल कमिशन ऑफ ज्यूरिस्ट','संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग' जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों का हनन जारी है आज भी नस्ल के आधार पर,रंग के आधार पर,गैर मूल के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। फर्क महज इतना है कि इन देशों का नागरिक समाज मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए प्रतिरोध करता है और हम भारतवासी मानवाधिकारों के हनन और हिंसक घटनाओं को अपने - अपने (धर्म, जाति,वर्ग, लिंग) कंफर्ट जोन से देखने समझने की कोशिश करते हैं। भारत में मानवाधिकारों और अधिकारों के हनन का बहुत ही मार्मिक चित्रण माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु जी ने वर्ष 2022 के संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अपने वक्तव्य में व्यक्त किया था। माननीय महामहिम द्वारा सरल सहज शब्दों में कास्ट,क्लास और जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को,समान न्याय और समय पर न्याय न मिल पाने के कारण उनसे उत्पन्न विसंगतियों की और भी ध्यान आकर्षित किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के आंकड़े भी माननीय महामहिम की चिंता को जायज ठहराते है। भारत की सभी जेलों में 76 प्रतिशत विचाराधीन कैदी है जो 10 से 15 वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्लास के आधार पर 73 प्रतिशत एस सी, एस टी,ओबीसी वर्ग से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत निम्न है तथा जिनके पास जमानत के पैसे भी नहीं है। इस स्थिति का वर्णन फिल्म 'जय भीम' में भी किया गया है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया और समान न्याय की अवधारणाओं के भेद को भी बखूबी से बयान किया गया है। आज कल हम DNTs (डिनोटिफाइड ट्राइब्स) पर काफी चर्चा कर रहे हैं जिन पर कभी अलग से विमर्श नहीं किया गया है। इन ट्राइब्स के लोगों को जन्मजात अपराधी माना जाता रहा है। 'दिल्ली क्राइम' वेब सीरीज के दूसरे सीजन में डिनोटिफाइड ट्राइब्स को केंद्र में रखा है और उनके विरुद्ध बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने का काम भी किया गया है। आज कल कई विद्वानों को भी इसी (वेब सीरीज) के संवादों को दोहराते हुए आपने भी सुना होगा। इस वेब सीरीज में खास बात यह है कि जिस डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है तो इन्ही के समुदाय का व्यक्ति जो पेशे से वकील है और कामयाब भी है जिसकी सामाजिक हैसियत इनसे अलग है लेकिन वो अपने समुदाय को और लोगों को नहीं भूलता है और उनके साथ होने वाले अन्यायों के खिलाफ और उनके अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक हैसियत उसकी सामाजिक हैसियत को भी निर्धारित करती है जिससे वह अपने कास्ट,क्लास के लोगों को उनके रोजमर्रा के संघर्षों को भूल जाता है। कुछ लोगों को अपवाद माना जा सकता है जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े है और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत में भी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में जो धर्म,जाति और लिंग आधारित हिंसक घटनाएं घटित हो रही है वे मानवाधिकारों की अवधारणा के विरुद्ध है लेकिन इनके खिलाफ किसी प्रकार का वक्तव्य आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता और न ही मानवाधिकारों के हनन के प्रति चिंता जाहिर की जाती है। मानवाधिकार आयोग के अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी संगठन और चंद मुट्ठी भर सक्रिय लोग हैं जो मानवाधिकारों के उल्लंघन को प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं तथा आम आवाम को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम भी करते हैं साथ ही अन्य लोगों के अधिकारों के हनन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करने का साहस भी प्रदान करते हैं। हम मानवाधिकारों को मानवाधिकार दिवस की प्रासंगिकता को किस रूप में देखते समझते हैं यह हमारे स्व-विवेक पर निर्भर करता है इसलिए विवेक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करते रहना हमारे मानवीय अस्तित्व को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है।

मानवाधिकार दिवस पर विशेष

वैश्विक मानवाधिकारों की क्रूर सच्चाई

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की आज चर्चा हो रही है। 'सभी के लिए न्याय' यह वर्षों से मांग हो रही है लेकिन हमारे आकाश, पृथ्वी और मनुष्य के वैयक्तिक अंतस को छलनी करने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस की थीम रखी गयी है-हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी। जिसका तात्पर्य है कि बिना किसी देरी के, यानी तत्काल अपने मानव अधिकार और भविष्य की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हों।

संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक जनमानस के लिए तैयार की गयी इस थीम का असर कितना होता है, यह सभी जानते हैं। राज्य संयुक्त राष्ट्र की दी हुई थीम का वर्ष भर मज़ाक उड़ाते हैं दुखद यह है। इससे वे अपना दुर्भाग्य आमंत्रित करते हैं। अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में डालते हैं। कदाचित उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता। विश्व में तो युद्ध चल रहे हैं फिर किस मानव अधिकार की रक्षा की बातचीत हो रही है? कौन से पर्यावरण की चिंता हो रही है? कौन से भविष्य की बातचीत की जा रही है, सोचें जरा!

विगत 10 वर्षों की थीम पर ही हम ध्यान केन्द्रित करें तो संयुक्त राष्ट्र ने क्रमशः दुनिया को कई नए नारे दिए और राज्यों सहित विश्व की बौद्धिकसमूह व जनसमूह से अपील की कि मानव अधिकारों की रक्षा करो। सन् 2015 में हमारे अधिकार, हमारी आज़ादी, हमेशा, आज किसी के अधिकारों के लिए खड़े हों, 2016, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 70 वर्ष, 2017, आइए समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए खड़े हों, 2018, मानव अधिकारों के लिए खड़े युवा, 2019, बेहतर तरीके से उबरें-मानवाधिकारों के लिए खड़े हों, 2020, समानता-असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, 2021, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, 2022 विगत वर्ष यानी 2023 में स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय और इस वर्ष भविष्य की चिंता की बात की गयी। अगले वर्ष एक नया नारा होगा। अतीत देखकर एक फिल्म में एक गाना याद आता है- कसमें, वादे प्यार वफ़ा के...आज वही हाल इन नारों का है। बड़े पैमाने पर विगत एक दशक में मानवाधिकारों के हनन हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विश्व में राज्यों ने अपनी सारी सीमाएं मानवाधिकारों के हनन की लांघ दी। कई राज्यों ने अति कर दी। क्या यही नारे ही अब हमारे मानवाधिकारों के पर्याय मात्र रह गए हैं, सवाल यह है?

आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, राइट नाऊ, यह इस वर्ष खूब दुहराए जाएंगे, लेकिन क्या यथार्थ में हमारे पृथ्वी पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाये जाएंगे? क्या युद्ध बंद होंगे? क्या जलवायु परिवर्तन की चिंता को गंभीरता से लिया जायेगा? क्या अफगानिस्तान में महिलाओं को आज़ादी मिलेगी? क्या शरणार्थियों की समस्या को उनके यथार्थ के साथ समझा जाएगा? क्या गरीबी, भुखमरी के निदान ढूँढे जायेंगे? क्रूर हिंसात्मक कार्रवाइयाँ क्या रुकेंगी? भारत में सबकी सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारियां सुनिश्चित होंगी? ऐसे अधिसंख्य सवाल हैं जो विश्व मानव अधिकार दिवस पर हमारे सामने प्रेत की तरह खड़े हैं। इनका निदान आखिर कब और कौन करेगा?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस यह दावा करती है कि प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, प्रभाव, सफलताओं और व्यावहारिक समाधानों का प्रदर्शन करके मानवाधिकारों के वास्तविक प्रभाव को वह दिखाएगी। उसका यह दावा है कि उसने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के साथ एक निश्चित यात्रा तय की है और वह समाधान की ओर बढ़ रही है। वोल्कान टुर्क जो कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त हैं उनका विश्वास है कि मानवाधिकार व्यक्तियों और समुदायों को बेहतर कल बनाने के लिए सशक्त बना सकता है। जिस दुनिया को हम चाहते हैं उसके रास्ते को व मानवाधिकारों की पूरी शक्ति को अपनाने और उस पर भरोसा करके, हम अधिक शांतिपूर्ण, समान और टिकाऊ बन सकते हैं। लेकिन प्रश्न वही है कि इनकी सुनता कौन है? इन्हें गंभीरता से लेता ही कौन है? यदि वोल्कान टुर्क इतने ही असरकारक होते तो विश्व में इतने बड़े पैमाने पर हिंसात्मक गतिविधियाँ न होतीं और सभी सुरक्षित भी महसूस करते। हाँ, उनकी जो आशाएं हैं कि इस बार, हम आशा करते हैं कि हम सभी को मानव अधिकारों के महत्व और प्रासंगिकता को स्वीकार करने, नकारात्मक रूढ़ियों और गलत धारणाओं का मुकाबला करके धारणाओं को बदलने और मानव अधिकारों के लिए एक वैश्विक आंदोलन को फिर से मजबूत करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे, यह ठीक लगता है। वह प्रयास करने के लिए और आशाओं को बनाये रखने के लिए निःसंदेह स्वतंत्र हैं लेकिन यदि वे निर्णायक परिणाम भी लाने में सफल होते तो निःसंदेह हमारी पृथ्वी का भाग्य बदल जाता और विश्व की 8 अरब से अधिक नागरिकों को अपने जीवन का सच्चा सुख मिलता।

वोल्कान टुर्क ने स्वयं स्वीकार किया है कि संघर्ष और संकट में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा हमारी दुनिया में सबसे क्रूर और घृणित अपराधों में से एक है। सार्वभौमिक निंदा के बावजूद राजनीतिक दमन जारी है। इज़राइल, गाजा, सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हैती और उससे आगे तक, महिलाओं और लड़कियों को आतंकित किया जा रहा है। उनके साथ क्रूरता की जा रही है। उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है। बलात्कार किया जा रहा है। हिरासत में लिया गया है। उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से इनकार किया जा रहा है और व्यवस्थित रूप से दुर्व्यवहार किया गया। अब आप सोच लीजिए कि दुनिया की वास्तविक सच्चाई क्या है? आधी आबादी कितना ज्यादा संकट में है? फिलिस्तीन में स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है। अक्टूबर 2023 से गाजा में कम से कम 43,000 लोग मारे गए हैं। इनमें 70 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। 101,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लगभग 1.9 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं जिनमें नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग लोगों में से कईलोग कई बार विस्थापित हुए हैं। अनगिनत लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह हाल ही में महासभा की चौथी समिति न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी, उसमें मानवाधिकार के लिए सहायक महासचिव इल्ज़ ब्रांड्स केहरिस कह रहे हैं। सोचिये दुनिया के हालत इस प्रकार के हैं और मानव अधिकार की रक्षा की हम बात कर रहे हैं और भविष्य सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं जो कि कितना हास्यास्पद है।

एशिया, यूरोप, गल्फ़ कंट्रीज, सभी जगह तो कोहराम मचा है फिर सवाल यह है की दुनिया में शांति फैलेगी कैसे और मानवाधिकारों का संरक्षण होगा कैसे? सच यह है कि विश्व के हालात को ठीक करने की कमजोर मुहिम और कमजोर इच्छाशक्ति ने हमें ज्यादा कमजोर और बेचारा बना दिया है। हमें लगातार अपने को अनुकूलित करने और नवप्रवर्तन करने की आवश्यकता है जो कि हो नहीं पा रहा है। ऐसे में, विश्व में गहराता सभ्यता संकट, कठिन होती जा रही जलवायु सुरक्षा, मनुष्य के वैयक्तिक व सामूहिक अधिकार के प्रश्न हमें चिढ़ा रहे हैं। यदि समय रहते सही में सपूर्ण विश्व के लोग मानव अधिकारों व गरिमा की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम यूं ही कोसने के लिए बाध्य होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पूरा विश्व वैश्विक विश्वास जुटाकर आगे बढ़े और जो विनाशकारी गतिविधियाँ चल रही हैं उसे रोककर सबके हितों के लिए अपनी इच्छाशक्ति व कर्तव्य का निर्वाह करें। वैशिक स्तर पर मानव हितों के लिए निवेश की ज़रूरत है और यदि निवेश नहीं किया गया तो आज जो परिस्थितियां हमारे सामने थोड़ी बौनी दिख रही हैं, वे कई अनुपात में अपना पाँव पसारेंगी।

जुआ खेलते पांच लोग धराये

बैतूल। पुलिस ने जुआ खेलते हुए पांच लोगों को पकड़ा है। जिन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाही की है। पुलिस ने धनोरा ब्रिज के पास कार्रवाई करते हुए जुआरियों से नकदी और ताश की गड्डियां जब्त की गई हैं। टीआई रविकांत डहरिया ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने ग्राम दनोरा ब्रिज के पास जुआरियों के ठिकाने पर दबिश देकर पांच आरोपियों को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़ा है। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जुआरियों के ठिकाने की जानकारी एकत्र कर ग्राम दनोरा ब्रिज के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पंकज काले (27) निवासी कोलगांव, सुखनंदन (35) निवासी चारसी (हाल निवासी बैतूल), राहुल इवने (19) निवासी चारसी (हाल निवासी सदर, बैतूल), मोहन (24) निवासी चारसी और कृष्णा बाघमोडे (44) निवासी कोलगांव को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों को खेड़ी पुलिस चौकी से ही जमानत दे दी गई।

शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में

फिल्म देखने के दौरान युवकों के बीच विवाद में निकल आया चाकू

बैतूल। टॉकीज में फिल्म देखने आए युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद में चाकू तक निकल आये। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट और बलवा दंगा करने का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें एक युवक को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक युवक सारणी के कांतिशिवा टॉकीज में पुष्पा 2 देख रहा था। इसी दौरान उसने सामने की सीट पर पैर रख दिया। वहां बैठे युवकों को नागवार गुजरा। उन्होंने पैर रखने वाले युवक को बाहर ले जाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक युवक चाकू निकालकर हमला करना चाह रहा था, लेकिन वहां मौजूद एक पार्षद ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। बताया जा रहा है कि फिल्म खत्म होने के बाद घर लौट रहे युवक को दोबारा नगरपालिका चौराहे पर पीटा गया। उसके बाद वह घर चला गया, लेकिन रात तीन बजे फिर कुछ युवक उसके घर पहुंच गए। जिस पर पीडित युवक की मां ने डायल हंड्रेड को काल कर मौके पर बुला लिया। जिससे आरोपी युवक भाग निकले। युवक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। सारणी टीआई देवकरण डहरिया ने बताया कि रविवार रात कुछ युवक कांति शिवा क्षविगृह में पुष्पा 2 फिल्म देखने गए थे। यहां एक युवक का वहां फिल्म देख रहे दो युवकों से विवाद हो गया। शो के बाद टॉकीज हॉल से बाहर आकर वे आपस में झगड़ रहे थे। वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट और एक युवक चाकू लिए नजर आ रहा है।

19 दिसंबर को बैतूल जिले में संभाग स्तरीय कार्यक्रम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होगे शामिल, विकास कार्यो का करेंगे लोकार्पण एवं भूमिपूजन

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व अंतर्गत 19 दिसंबर को बैतूल आएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव के मुख्य आतिथ्य में पुलिस परेड ग्राउंड में संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा संभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा प्रमुख रूप से स्व सहायता समूह और विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव के मुख्य आतिथ्य में प्रस्तावित कार्यक्रम की सोमवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में सभी अधिकारियों को जानकारी दी और निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल, मंच व्यवस्था, हेलीपैड स्थल पर सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

रात 3 बजे वन विभाग की सतर्कता से पकड़ी गई सागौन लकड़ी, आरोपी गिरफ्तार

भैंसदेही के पास अवैध सागौन से लदी बोलेरो पकड़ी

बैतूल। दक्षिण बैतूल (सामान्य) वनमंडल के सावलमेंढा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की सतर्कता से सागौन तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल विजयानन्तम टी.आर. और उपवनमंडलाधिकारी, भैंसदेही (सामान्य) देवआनंद पाण्डेय के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी मानसिंग परते के निर्देशन में गश्ती दल ने रात करीब 3ः15 बजे ग्राम आडाउम्बर के पास बैलाकांडी

क्षेत्र में एक संदिग्ध वाहन को रोका। गश्ती दल ने देखा कि कच्चे रास्ते पर सिंगल हेडलाइट के साथ एक वाहन आ रहा था। रोके जाने पर महिंद्रा बोलेरो पिकअप (क्रमांक एमएच-27-बीएक्स-7069, सफेद रंग) में 23 नग अवैध सागौन लकड़ी पाई गई। साथ ही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर (क्रमांक एमपी-48-एमएच-8267, जामुनी रंग) भी मौके पर मिली। जब्त लकड़ी का माप 1.639 घन मीटर पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 91,838 रुपये है। वन परिक्षेत्र सावलमेंढा के कैंपस में वाहन और लकड़ी को ले जाकर अपराध प्रकरण क्रमांक 499/32 दिनांक 9 दिसंबर 2024 को पंजीबद्ध किया गया। आरोपी कमल पिता नेमीचंद उईके, निवासी आडाउम्बर, तहसील भैंसदेही के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है। इस कार्यवाही में देवीराम उईके वनपाल, परिक्षेत्र धाबा, महेंद्र पाल वनपाल, परिक्षेत्र कोथलकुंड, गौरव कुमार जैन वनरक्षक, रामू धुर्वे वनरक्षक, अंकित नाडेकर वनरक्षक और सुरक्षा श्रमिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वन विभाग की तत्परता और समर्पण से यह बड़ी कार्रवाई सफल हुई।

लोगों को ठगने साइबर ठग अपना रहे नये-नये तरीके, सावधानी जरूरी

● जिले में भी बढ़ रहा साइबर अपराध, 14 मामले पंजीकृत, 16 गिरफ्तार

संजय द्विवेदी, बैतूल। आज के समय में इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है, विशेषकर युवाओं में, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ गया है। देश-प्रदेश और जिले से लेकर कस्बों तक लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए है और हो भी रहे है। कुछ लोग अज्ञानतावश, तो कुछ लोगों को साइबर ठग भय-लालच देकर शिकार बना रहे है। ठगी के शिकार लोगों की फेहरिस्त में उद्यमी-कारोबारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी से लेकर छोटे व्यापारी शामिल है। साइबर ठग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। समाज के हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से चंगुल में ले रहे हैं। इनसे सतर्क रहने के लिए पुलिस और सायबर सेल समय-समय पर लोगों को जागरूक भी करती है, लेकिन ठग, ठगी के नये-नये तरीके निकाल ही लेते है। यदि बैतूल जैसे छोटे से जिले की ही बात करे तो, यहां भी सायबर ठगों ने लोगों को अपना निशाना बनाया है। पिछले 11 महीने में 14 मामले सायबर सेल में पंजीकृत हुए है। इसके अलावा फ्रॉड कॉल के भी कई मामले सामने आये है। साइबर ठगों ने कस्टम अधिकारी, तो कभी पुलिस अधिकारी, ईडी अधिकारी बनकर मामले में घेरने का प्रयास किया। यह लोग फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराते-धमकाते है और अपना निशाना बनाते है। लोग भी डर की वजह से आसानी से इनका शिकार बन जाते है। ऐसे मामलों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया ने डराने-धमकाने और फॉड कॉल आने पर पुलिस की मदद लेने और जागरूक रहने की सलाह दी है।

ठगी के मामले में 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सायबर सेल बैतूल ने ठगी के विभिन्न मामलों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साइबर सेल प्रभारी अश्विन चौधरी ने बताया कि साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतों की हर एंगल से पडताल की जाती है। फ्रॉड कॉल करने वाले मोबाइल नंबरों पर भी पुलिस की नजर रहती है। ठग खासकर लोगों के मोबाइल पर अनजान नंबरों से कॉल करते है। अधिकांश घटनाओं में उन्हें खुद के या परिजन के किसी केस में फंस जाने की बात कहकर डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे मामलों में सामने से कॉल करने वाला खुद को पुलिस बताता है। डर के मारे घबराए लोग इनके बताए खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस को भी देरी से सूचना देते है।

पुलिस और साइबर सेल चला रहा अभियान..

साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए साइबर सेल और पुलिस निरंतर अभियान चला रही है। लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग लालच-डर और अज्ञानतावश उनके शिकार बन जाते है। सब इंस्पेक्टर साइबर सेल अश्विन चौधरी ने बताया कि बैतूल पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झारिया के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें स्कूल, कॉलेज सहित अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

साइबर ठगों से बचने इन बातों का रखे ध्यान

1. बैंक संबंधित जानकारी किसी से भी शेयर न करे।
2. धमकी भरे फोन आने पर पुलिस को सूचना दे।
3. अनजान वीडियो कॉल पर किसी कॉल का जवाब न दें।
4. यदि भ्रमित हैं, तो फोन बंद कर दें और उस नंबर को ब्लॉक कर दें।
5. नीले रंग में लिखे गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
6. लिंक पर क्लिक करने से पहले हमेशा जांचें कि क्या ऐसे पात्र सरकारी पोर्टल हैं, सहित अन्य।

साइबर ठगों ज्यादातर अपनाते है यह तरीके .....

1. डिजिटल अरेस्ट - स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं। वे लोगों को किसी भी आरोप में शामिल होने का दावा करते हैं। जिसके बाद लोग डरकर स्कैमर के झांसे में फंस जाते है।

2. जॉब स्कैम - ठग ज्यादा नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करते है। साइबर ठग फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज व लिंक्स भेजते हैं। इसके बाद ठग फीस या ज्वाइनिंग किट के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं।

3. लकी ड्रॉ स्कैम - साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं। मैसेज में प्राइज मनी का लालच दिया जाता है। जो लोग लालच में आ जाते हैं, ठग उन्हें अपना शिकार बना लेते है।

4. पार्सल स्कैम - साइबर ठग लोगों को कॉल कर झांसा देते हैं। बताते हैं कि उनका कोई पार्सल आ रहा था, जिसमें ड्रग्स पाए जाने से उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। लोग डरकर ठग को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं।

5. कैश ऑन डिलिवरी स्कैम - साइबर ठग असली शॉपिंग एप जैसी मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। यहां से खरीदारी करने पर लोगों के पास फर्जी या गलत प्रोडक्ट पहुंचता है। जैसे मोबाइल खरीदने पर पत्थर या कुछ और।

6. सोशल मीडिया पर बदनामी - साइबर ठग किसी लडक़ी की मदद से लोगों को शिकार बनाते हैं। बाद में बदनामी की धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उन्हें निशाना बनाकर ठगी करते हैं।

इनका कहना है -

लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने की आवयकता है। कोई भी अनजान नंबर से कॉल आता है या धमकी दी जाती है। डराया जाता है, तो इसकी शिकायत साइबर सेल या पुलिस को करनी चाहिए। ऐसे मामलों की शिकायत लोग टोल फ्री नंबर 1930 या वेबसाइड पर जाकर भी कर सकते है।

- अश्विन चौधरी, सब इंस्पेक्टर, साइबर सेल, बैतूल

साइबर सुरक्षा व डिजिटल साक्षरता विषय पर कार्यक्रम आयोजित

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में प्रारंभ जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए सोमवार को साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाहपुर की परियोजना अधिकारी श्रीमती दीपमाला अहाके द्वारा सीएम राइज मिडिल स्कूल शाहपुर के बालक-बालिकाओं को डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और उन्हें संचालित करने की क्षमता के रूप में साइबर सुरक्षा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा और प्रणालियों को खतरों से बचाने के लिए प्रयास किये जाने विस्तृत चर्चा की

गई। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार अपने कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, टैबलेट और इंटरनेट से जुड़े किसी भी अन्य डिवाइस को किस प्रकार हैकिंग, फिशिंग और अन्य के रूप में हो रहे साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है। इसके अलावा परियोजना बैतूल ग्रामीण अंतर्गत स्कूल डिवाइन इंग्लिश स्कूल बैतूल बाजार में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और पहुँच प्रबंधन संगठनों, व्यक्तियों को साइबर हमलों से बचाने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं संबंधी समझाइश दी गई। कार्यक्रम में विभागीय पर्यवेक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, लघु नाटिका की बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति

शाहपुर। ग्राम पंचायत कुंडी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मर्दानपुर के माध्यमिक शाला के बच्चों द्वारा विकासखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की। अब बच्चे विकासखंड स्तर के बाद जिला स्तर के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। छोटे से ग्राम मर्दानपुर की माध्यमिक शाला के बच्चों के द्वारा अति सुंदर पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम कि यह लघु नाटिका प्रस्तुत की गई थी। इसमें माध्यमिक शाला मर्दानपुर के शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग रहा । बच्चों के द्वारा जिला स्तर पर भी अच्छा प्रयास और प्रस्तुति दी जाएगी।

वाहन रैली से दिया योग आरोग्य का संदेश

बैतूल। स्वच्छता से वातावरण की शुद्धि, गीता पाठ से आध्यात्मिक ज्ञान और योग आरोग्य से तन मन स्वस्थ रखने की त्रिवेणी का संदेश शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने एक मंच पर दिया। आगामी 13, 14 और 15 दिसंबर को योग ऋषि स्वामी रामदेव के परम शिष्य और पतंजलि योगपीठ के केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव महाराज के मार्गदर्शन में होने वाले योग आरोग्य शिविर के प्रचार के लिए ओपन ऑडिटोरियम में होने वाली नियमित योग कक्षा के बाद सभी योग साधक जेएच कॉलेज पहुंचे, वहां बबलू दुबे के मार्गदर्शन में 75 कदम के साथियों तथा कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को भारत स्वाभिमान के जिला अध्यक्ष सुनील कुबड़े, आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील द्विवेदी ने शिविर में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में आमला से पधारे सचिन मदान व्दारा पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए संचालित पत्तल दोने के स्टार्टअप को जन अभियान परिषद के राज्य उपाध्यक्ष मोहन नगर, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल कॉलेज प्राचार्या डॉ श्रीमती चौबे, जन भागीदारी के घनश्याम मदान, विकास नगर

पार्षद आनंद प्रजापति द्वारा सम्मानित किया गया। दोपहर में ओपन ऑडिटोरियम में प्रयागराज में होने वाले हरित कुंभ में एक थैला एक थाली अभियान के तहत भेजे जाने वाली थैली और थालियां का पूजन किया गया साथ ही गीता के 12वें अध्याय का सामूहिक वाचन के साथ जन जन तक योग आरोग्य का संदेश पहुंचाने के लिए वाहन रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मुख्य मार्गो से होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंची। वाहन रैली में शुभा तिवारी,अरुणा पाटनकर, कृष्णा अमरुते, शिखा बारस्कर, चंद्रभागा भूमरकर, निर्मला गोहिया, संगीता तहकित, युवा भारत के हितेश पटेल, विमल दुबे, संजय शुक्ला सहित बड़ी संख्या में योग साधक और आमजन सम्मिलित रहे।

योजनाओं में वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए: कलेक्टर

मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक होगा संचालित

बैतूल। मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समयसीमा की बैठक में बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की विस्तार से समीक्षा की। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग अंतर्गत संचालित हितग्राही और स्वरोजगार मूलक योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में इन पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित कराएं। शिविर के आयोजन से पूर्व ही पात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन सभी विभाग द्वारा किया जाएं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अभियान अंतर्गत सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट कार्य कर शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करें। पूरी तत्परता एवं गंभीरता से अभियान का क्रियान्वयन किया जाए। सभी अधिकारी हर दिन निर्धारित पोर्टल पर अपनी प्रगति रिपोर्ट करेंगे, जिसकी प्रदेश स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए शिविर प्रभारी और समन्वयक दल और उनकी मॉनिटरिंग के लिए विकासखंड स्तर पर सेक्टर अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए डाटा संकलन और आवश्यक समन्वय के लिए तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम गठित कर उन्हें सक्रिय किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी एसडीएम एवं सीईओ जनपद प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिए कि अभियान के तहत पूर्व से लंबित आवेदन और शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए। राजस्व महाअभियान 3.0 भी अब 26 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाए। आयुष्मान योजना अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जाए। साथ ही डाटा संबंधी विसंगतियों को भी सुधारें। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि कोई भी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कोताही न बरते। उन्होंने श्रम, जल संसाधन, लोक निर्माण, वन एवं राजस्व विभाग को शिकायतों के निराकरण में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक शिकायतों वाले विभाग प्राथमिकता से अपनी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन ने बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी एवं अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अभियान के सुचारू संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अपर कलेक्टर एवं पीओ डूडा/नोडल अधिकारी रहेंगे विभिन्न योजनाओं के साथ आयुष्मान योजना संबल योजना में सैचुरेशन हासिल किया जाएगा। अभियान चलाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ जनहित में बेहतर कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा।

13 दिसंबर को जेएच कॉलेज में केंपस ड्राइव

- बैठक में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रोहित डावर ने बताया कि जिले में आगामी 13 दिसंबर को जेएच कॉलेज में केंपस ड्राइव का आयोजन होगा। जिसमें विभिन्न कंपनियों के साथ स्वरोजगार मूलक योजनाओं से युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। जिला आयुष अधिकारी द्वारा 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक संचालित देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर राजीव निरंजन श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

ऊर्जा मंत्री के भाई देवेंद्र तोमर का निधन

सीएम ने कहा-भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति अंतिम संस्कार में शामिल हुए सिंधिया-तोमर

ग्वालियर (नप्र)। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र तोमर का रविवार रात भोपाल के चिरायु अस्पताल में निधन हो गया। उनको लंग्स में इंफेक्शन था, जिसके चलते रविवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर ग्वालियर से एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के (कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) हॉस्पिटल में भर्ती करने ले जा रहे थे। रास्ते में हालत बिगड़ने पर भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई और भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को एक्स पर लिखा- साथी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर के रूप में आज भाजपा ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता को खो दिया। उनका सम्पूर्ण जीवन जन सेवा के प्रति समर्पित रहा। उनका निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्यात्मा को शांति दें। शोकाकुल परिवार को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करें।

2009 में रह चुके नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष- भाजपा नेता देवेंद्र तोमर तीन बार नगर निगम परिषद में पार्षद निर्वाचित हुए हैं। वह साल 2009 में नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनकी एक बेटी व बेटा है। बेटी जज है और बेटा रेस्टोरेंट का संचालन करता है। असल मायने में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के राजनीतिक गुरु उनके बड़े भाई देवेंद्र तोमर ही थे।

कंटेनर ट्रक को लूट बदमाशों ने लाखों के माल पर किया हाथ साफ

भोपाल। 11 मील टोल के पास बदमाश ड्राइवर को शराब पिलाकर कंटेनर ट्रक लूट भागे। ड्राइवर ने वारदात की जानकारी कंटेनर ट्रक के मालिक को रास्ते में फोन कर दी। जानकारी देने के बाद ड्राइवर भी लापता हो गया है। उसका मोबाइल भी हुआ उसका बंद आ रहा है। ट्रक मालिक को कंटेनर ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर डिवाइन स्कूल के पास लावारिस हालात में मिला। कंटेनर ट्रक में 11 लाख की मैग्गी बदमाश ले भागे ट्रक के 3 टायर फोड़ दिए और सारा डीज़ल भी निकाल ले गए। ट्रक मालिक ने बिलखिरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवक ने फांसी लगाई

भोपाल। बैरागढ़ थानाक्षेत्र में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एफ़ वार्ड में किराए से रहने वाले 25 साल के युवक ने घर मे फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम प्रियांशु सिंह बताया गया है ,जो यहां रह कर पढ़ाई, कर रहा था। पुलिस कर रही मामले की जांच कर रही है।

अयोध्या नगर में चाकू घोंपकर युवक की हत्या

भोपाल। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में तीन युवकों ने मनोज कुशवाहा नामक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने प्रहलाद कुशवाहा, राजू कुशवाहा समेत तीन को बनाया आरोपी है। पुलिस ने दो आरोपियों को कस्टडी मे लिया है। एक अन्य युवक की तलाश जारी है। घटना रात तीन बजे की बताई जा रही है। पुलिस हत्या के अन्य एंगल पर भी जांच कर रही है।

पतंगबाजी में उपयोग वाले चाइनीज मांझे पर रोक

भोपाल। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र चारी ने एक आदेश जारी कर आगामी मकरसंक्रांति के मद्देनजर चाइनीज मांझे के उपयोग पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि आगामी त्यौहार के मद्देनजर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश में चाइनीज मांझे से कई पशु-पक्षी की मौत हो चुकी और कई वाहन चालक घायल हुए हैं। आदेश में जिक्रहै कि किसी संस्था या पक्ष को आपत्ति तो वह सीधे पुलिस कमिश्नर को विधिवत तरीके से आवेदन कर सकता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और यह आगामी 2 माह तक लागू रहेगा।

भोपाल में 19 साल के युवक ने किया सुसाइड

परिजन बोले- प्रेम प्रसंग में दी जान; पुलिस जांच में जुटी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र इलाके में स्थित अन्ना नगर में रहने वाले युवक ने सोमवार की सुबह घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट नहीं

मिलने से आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की बात कही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजालदे ने बताया कि रोहन मोरे (19) अन्ना नगर में रहता था। वह भोपाल मेले में स्थित एक चाइनीज फूड के काउंटर कर्मचारी के तौर पर काम करता था। सोमवार की सुबह उसने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एफएसएल की टीम से घटना स्थल का मुआयना करा लिया है। जहां कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की बात सामने आई है। मृतक के मोबाइल फोन को जब्त किया है। जिसका परीक्षण कराया जाएगा।

भोपाल में चौथी लाइन के लिए टूटेंगी झुग्गियां-दुकानें

विरोध में कलेक्टोरेट पहुंचे मोतीनगर के लोग; बोले- एक के बाद एक आ रहे नोटिस

भोपाल (नप्र)। भोपाल के सुभाषनगर विश्राम घाट के पास मोतीनगर की 381 झुग्गियां और करीब 100 दुकानें हटाई जाएंगी। इसके लिए एमपी नगर एसडीएम एलके खरे ने नोटिस भी दिए हैं। यह झुग्गियां और दुकानें चौथी लाइन के लिए टूटेंगी। दूसरी ओर, इन्हें तोड़ने का विरोध भी शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्टोरेट पहुंचे।

लोगों ने कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से उन्होंने कहा कि, जिला प्रशासन एक के बाद एक नोटिस थमा रहा है। इससे हम भयभीत है। मोतीनगर में छोटी-मोटी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की दुकानें भी हैं। जिनके माध्यम से वहां के लोग जैसे-तैसे अपना जीवन यापन करते हैं।

लोगों को हटाया तो वे बेघर हो जाएंगे

कांग्रेस नेता शुक्ला ने कलेक्टर सिंह से कहा कि, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले

वादा भी किया था कि जो जहां निवास कर रहे हैं, उन्हें वहीं बसाया जाएगा। फिर मोतीनगर बस्ती को बिना व्यवस्थापन के क्यों हटाया जा रहा है? यदि झुग्गियां हटती है तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। चौथी लाइन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोतीनगर के रहवासियों को उचित स्थान पर व्यवस्थापित (शिफ्ट) किया जाए। नई जगह पर सभी मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं भी हों।

अनिश्चितकालीन धरना देंगे

शुक्ला ने कहा कि इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जल्द ही वे पूर्व मुख्यमंत्री चौहान के बंगले के बाहर रहवासियों के साथ अनिश्चितकालीन धरना देंगे और उन्हें उनका वादा याद दिलाएंगे। कलेक्टोरेट के घेराव के दौरान तारिक अली, अमित खटीक, मुजाहिद सिद्दीकी, शानू खान, जहीर कुरैशी, जाकिर कुरैशी, अलीम उद्दीन बिल्ले, मो. राजिक, आशुतोष बिजोर, अनीस सलमानी, केशव मौरे, नीलोफर खान, नन्हें खान, खालिद कुरैशी आदि मौजूद थे।

भोपाल कलेक्टर ने सस्पेंड किए 3 पटवारी

तीनों पर निजी ऑफिस से काम करने, घूस लेने का आरोप, एडीएम सौंपेंगे जांच रिपोर्ट

भोपाल (नप्र)। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भोपाल के 3 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। एडीएम सिद्धार्थ जैन को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इन पटवारियों ने अपनी निजी दुकानें खोल ली थी। वे घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। जिन पटवारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें किशोर दांगी, पवन शुक्ला और निधि नेमा शामिल हैं। एडीएम जैन को मामले की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

यहां पदस्थ हैं तीनों पटवारी

किशोर दांगी, पटवारी बीनापुर। इन्होंने करौंद में पीपल चौराहा के पास निजी ऑफिस खोल रखा है।

पवन शुक्ला, पटवारी पुरा छिंदवाड़ा। इनका ऑफिस गोल मार्केट संजीव नगर में है।

निधि नेमा, नीलबड़ भौंरी की पटवारी हैं। जिनका ऑफिस चौबदारपुरा तलैया में है।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन

भोपाल। सोमवार 09 दिसंबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल में मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्रीमती एकता अरोड़ा के निर्देशन में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम' के विषय पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान मंडल कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों, नीतियों और रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने और कार्यस्थल को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड अब ऑनलाइन भी बनेंगे

जारी होने की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी; भोपाल रेल मंडल की पहल

रेलवे का दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही कार्ड भी ले सकते हैं। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया- भोपाल रेल मंडल का यह कदम सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ अधिक से अधिक योग्य यात्रियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल से 25 नवम्बर 2024) के बीच 518 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए गए हैं। इन रियायत कार्डों के जरिए दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ नियमानुसार सहायक के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

24 घंटे में साइबर ठगों ने 11.75 लाख ट्रांसफर कराए

फर्जी ऑफिसर बनकर बुजुर्ग दंपती को डिजिटल अरेस्ट किया, राजस्थान से आया कॉल

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपती को अपना निशाना बनाया। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान से रिटायर 62 वर्षीय एंथोनी प्रकाश और उनकी पत्नी को ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' करते हुए उनसे करीब 11 लाख 75 हजार रुपए ठग लिए।

ठगों ने खुद को फर्जी पुलिस अधिकारी बताकर दंपती को इतना डरा दिया कि वे उनकी हर बात मानते चले गए। हालात ऐसे बन गए कि उन्होंने साइबर ठगों को 24 घंटे के भीतर रुपए एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद भी ठगों का कॉल आता रहा। परेशान होकर बुजुर्ग दंपती ने अपने बेटे को कॉल किया और पूरी घटना बताई। बेटे ने जब जांच की, तो पता चला कि वे नकली पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने उनके साथ ठगी की थी। बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर रांझी थाना पुलिस और साइबर टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले 1.75 लाख और फिर 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए- रांझी थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी एंथोनी और उनकी पत्नी एग्रेश नीना पाल 1 दिसंबर की सुबह घर पर थे। इस बीच नीना पाल के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने

वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। जल्द ही दिल्ली पुलिस जबलपुर आकर उन्हें गिरफ्तार करेगी।

यह सुनकर नीना घबरा गईं और उन्होंने तुरंत अपने पति एंथोनी को जानकारी दी। इसके बाद ठगों ने एंथोनी को भी धमकी दी। ठगों से इतना डरने के कारण दोनों ने जैसा ठग कह रहे थे, वैसा ही किया।

घबराए दंपति 2 दिसंबर को बैंक जाकर 1.75 लाख और 3 दिसंबर को 10 लाख रुपए ठगों के खाते में एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए।

बेटे को सूचना पर हुआ खुलासा- ठगी के बाद भी ठग लगातार कॉल करते रहे, जिससे परेशान होकर दंपती ने दुबई में जॉब कर रहे अपने बेटे को पूरी घटना की जानकारी दी। बेटे ने जब इस बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि यह एक ठगी का मामला है।

पुलिस जांच में जुटी- 8 दिसंबर को बुजुर्ग दंपती ने रांझी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि कॉल राजस्थान से किया गया था। पुलिस और साइबर सेल की टीम अब ठगों का पता लगाने में जुटी हुई है।

एम्स भोपाल ने ब्रेन-डेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए शोक परामर्श पहल शुरू की

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में संस्थान ने ब्रेन-डेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कार्यक्रम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत संस्थान ने अपने फैकल्टी और स्टाफ के लिए एक संरचित शोक परामर्श पहल की शुरुवात की है। यह पहल ब्रेन-डेड दाताओं का प्रबंधन करने, शोकग्रस्त परिवारों का सहयोग करने में आने वाली भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को समझने और उन्हें संभालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शोक परामर्श सत्र एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा आयोजित किया गया। इस टीम में प्रत्यारोपण सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और शोक प्रबंधन के विशेषज्ञ परामर्शदाता शामिल थे।

प्रो. सिंह ने इस पहल के महत्व को समझाते हुए कहा, ब्रेन-डेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कार्यक्रम एम्स भोपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह कई जीवन बचा सकता है, लेकिन इसमें भावनात्मक चुनौतियों को समझना जरूरी है। ये सत्र हमारी टीम को संवेदनशीलता और पेशेवर तरीके से इन स्थितियों को संभालने के लिए तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम में डॉ. विजेंद्र सिंह, डॉ. सुनैना, डॉ. सुरेंद्र, डॉ. केतन और मनोवैज्ञानिक मोहित कुमार ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सत्र का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को शोकग्रस्त परिवारों से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बात करने और तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांति बनाए रखने के लिए तैयार करना था।

16 से शीतकालीन सत्र, दूसरे दिन पेश होगा पहला अनुपूरक बजट

कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी, आधा दर्जन विभागों के विधेयक भी होंगे पेश

भोपाल (नप्र)। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद दूसरे दिन मोहन यादव सरकार का चालू वित्त वर्ष का अनुपूरक बजट पेश होगा। इस बजट को मोहन सरकार सत्र शुरू होने के पहले मंजूरी देगी। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री के साथ बैठक की जा चुकी है। इस अनुपूरक बजट को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। इसके पहले सत्र शुरू होने पर पहले दिन सरकार की ओर से विधेयक पेश किए जा सकते हैं। विधानसभा सचिवालय ने पांच दिन तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए कार्ययोजना घोषित कर दी है। इसमें कहा गया है कि, पहले दिन सत्र शुरू होने पर प्रश्नोत्तर काल होगा और इसके बाद अलग-अलग विभागों के आधा दर्जन विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद 17 दिसंबर को सुबह प्रश्नोत्तर काल होगा और इसके बाद वर्ष 2024-25 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य शासकीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पर चर्चा तीसरे दिन होगी और इसी दिन एमपी विनियोग विधेयक 2024 पेश होगा। इसके अलावा सत्र के बाकी दिनों में प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

विधानसभा में लगे हैं 1070 ऑनलाइन प्रश्न- शीतकालीन सत्र के लिए इस बार विधायकों ने कुल 1070 ऑनलाइन सवाल विधानसभा के माध्यम से सरकार से किए हैं। वहीं 696 प्रश्न ऑफ लाइन किए गए हैं। कुल सवालों की संख्या 1766 है। इसमें तारांकित प्रश्न 888 और अतारांकित प्रश्न 878 हैं। तारांकित प्रश्नों को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में चर्चा में शामिल किया जाता है। इसमें रोज 25 सवाल तय रहते हैं जिसका जवाब सदन में विधायक के सवाल के बाद संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा दिया जाता है।

डबरा रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी सब-इंजीनियर की चप्पलों से पिटाई

युवती का आरोप- नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर की गलत हरकत

डबरा (नप्र)। डबरा में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की एक युवती ने चप्पलों से पिटाई कर दी। जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना डबरा रेस्ट हाउस की है, जहां इंजीनियर ने युवती को नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। आरोप है कि सब इंजीनियर रामस्वरूप कुशवाह पर युवती ने नौकरी का झांसा देकर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है।

दतिया निवासी रामस्वरूप कुशवाह डबरा में पदस्थ है। किसी परिचित ने उसे एक युवती से मिलवाया जिसे नौकरी की जरूरत थी। इंजीनियर उसे लगातार नौकरी का आश्वासन देता रहा। रविवार शाम उसने लड़की को डबरा रेस्ट हाउस

बुलाया था। युवती का आरोप है कि वह उसे कमरे में ले गया और गलत हरकत करने की कोशिश की। युवती ने इंजीनियर की नीयत को भांपते ही गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। वीडियो में युवती कहती सुनाई दे रही है कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे बहन बनाया था। कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। अभी पुलिस को बुलाती हूं। युवती ने पहले कमरे के अंदर, फिर रेस्ट हाउस के बाहर भी इंजीनियर को चप्पलों से जमकर पीटा। इंजीनियर ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन युवती ने परिसर से बाहर खींचकर भी उसकी पिटाई जारी रखी। मारपीट के बाद इंजीनियर मौके से भाग गया।

वीडियो हुआ वायरल, लेकिन नहीं दर्ज हुई शिकायत

इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवती ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। घटना के बाद सब-इंजीनियर रामस्वरूप कुशवाह ने कहा कि दो लोग महिला के साथ आए और मुझसे मारपीट की। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी तबीयत खराब है, बाद में बात करूंगा।

पुलिस का बयान

डबरा एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक युवती ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यदि शिकायत आती है, तो कार्रवाई की जाएगी।

राइट क्लिक

जनादेश बनाम ईवीएमादेश: मरकडवाडी की 'प्रोटेस्ट मॉकड्रिल' में निहित सवाल

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

चुनाव नतीजे अगर पक्ष में हो तो जनादेश और विपरीत हों तो ईवीएमादेश बताने के नरेटिव का एक बेहद नाटकीय लेकिन चिंताजनक प्रसंग महाराष्ट्र के मरकडवाडी गांव में परिणामों को नकारकर फिर से मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मॉकड्रिल का है। इससे चौंके प्रशासन ने हालांकि सख्ती के साथ इस मुहिम को फेल कर दिया, लेकिन आने वाले समय में हर नापसंद चुनाव परिणाम पर सवालिया निशान लगाकर इस तरह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की प्रवृत्ति जोर पकड़ सकती है। मरकडवाडी के ग्रामीणों का कहना है कि वहां भाजपा प्रत्याशी को जितने वोट मिले, वह संभव ही नहीं था, क्योंकि यह गांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) का गढ़ है। हालांकि यह चुनाव राकांपा (शरद) के उत्तमराव जानकर ने ही जीता, लेकिन सवाल इस बात पर उठाया गया कि हारे हुए भाजपा प्रत्याशी को भी इतने ज्यादा मत कैसे मिल गए? इसका दूसरा अर्थ यह है कि ईवीएम को मैनेज किया गया। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी नत्थी है कि जब ईवीएम को 'मैनेज' ही किया जाना था तो 'पूरी तरह' क्यों नहीं किया गया ताकि भाजपा प्रत्याशी राम सातपुते जीत ही जाते। मजे की बात यह है कि एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे के तहत विजयी उम्मीदवार जानकर ने त्यागी मुद्रा में कहा कि यदि चुनाव आयोग मरकडवाडी में बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने पर सहमत होता है तो मैं जीतकर भी विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। (अगर सही में चुनाव नतीजे संदेहास्पद थे तो उन्हें सशर्त इस्तीफे की पेशकश करने के बजाए सीधे इस्तीफा दे देना था) इसी नरेटिव के तहत ग्रामीणों ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में मतपत्रों के जरिए फिर से वोटिंग का ऐलान कर दिया, जबकि चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ निर्वाचन आयोग का है। कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमे ईवीएम तो क्या चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है। इसी के तहत राकांपा नेता शरद पवार 8 दिसंबर को मरकडवाडी पहुंचे और ईवीएम पर संदेह दोहराया। उधर कांग्रेस ने मरकडवाडी में लोकतंत्र की शहादत बताकर इस 'गांव की पवित्र मिट्टी' दिल्ली में राजघाट में बापू की समाधि पर अर्पित करने का ऐलान किया। यह मिट्टी गांव से एकत्रित कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।

दरअसल मरकडवाडी सोलापुर जिले की मालशिरस विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल गांव है। मालशिरस अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। हाल में राज्य में हुए विस चुनाव में इस सीट पर राकांपा (शरद) के उम्मीदवार उत्तमराव जानकर ने जीत हासिल की थी। नतीजों से चौंके मरकडवाडी के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तो जानकर को वोट दिए थे। लेकिन ईवीएम के आंकड़े बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा यानी 1003 वोट दिखा रहे हैं, जबकि राकांपा उम्मीदवार को 843 वोट। ये गलत है।

गांववालों का दावा था कि बीजेपी प्रत्याशी को 100-150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते। लिहाजा उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बैलट पेपर से फिर से मतदान की अपील की और कहा कि वो इसका खर्चा उठाने को तैयार हैं। साथ ही गांवावालों ने मॉक पोलिंग के लिए 3 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी। इससे घबराए प्रशासन ने सख्ती करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी। मॉक पोलिंग रोकी और दो सौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

मरकडवाडी की तर्ज पर अकोला जिले के दो गांवों तुलजापुर और बेलतला गांव में भी ईवीएम नतीजों को खारिज करते हुए फिर से मॉक पोल की मॉक पोल की मांग उठी। हालांकि इस मॉक पोल में मत पत्रों की जगह 'महायुति' व 'महाविकास आघाड़ी' लिखी दो मतपेटियां रखी जानी थी। इस मॉक पोल की पहल एक स्थानीय समाचार पत्र समूह के मालिक ने की थी। यह भी एक ड्रामा ही था। प्रशासन ने उसे भी रूकवा दिया। लेकिन असंतोष के इन सुरों के बीच अगर कुछ सच्चाई है तो चुनाव आयोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग की सक्षमता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर दूसरे कोणों से भी सवाल उठते रहे हैं। इसका जवाब भी चुनाव आयोग को ही देना होगा। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका है। लेकिन लगता है हमारे यहां ईवीएम अब मतदान की मशीन न होकर पराजित पक्ष के लिए हार के स्थायी ठीकरे के रूप में तब्दील होती जा रही है। मरकडवाडी की ही बात करें तो वहां राकांपा (शरद) के उत्तम जानकर ने भाजपा के राम सातपुते को कुल 13 हजार 147 वोटों से हराया था। जीत का यह अंतर काफी है। जानकर को ये वोट पूरे विधानसभा क्षेत्र से मिले थे। ऐसे में केवल मरकडवाडी गांव के मतदान को मुद्दा बनाकर मॉक पोलिंग करवाने की बात गले नहीं उतरती। इस बीच चुनाव नतीजों से शुरू में हताशा में डूबे शरद पवार भी मरकडवाडी पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की तर्ज पर चुनाव ईवीएम के बजाए बैलट पेपर से कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देशों में मत पत्रों के जरिए मतदान हो रहा है तो भारत में क्या दिक्कत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से राज्य की जनता खुश नहीं है। इस बयान के पीछे कई चुनाव लड़ चुके शरद पवार की यह पूर्वाग्रह है कि मतदाता जो मानस लोकसभा चुनाव में बनाता है, वही विधानसभा चुनाव नतीजों में भी परिलक्षित होता है। हकीकत में ऐसा हो, जरूरी नहीं है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे और तकाजे अलग-अलग होते हैं। दोनों में हमेशा एक से नतीजे आएं, यह जरूरी नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चार माह पहले देश के साथ राज्य की 47 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीतकर भारी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते पवार के प्रति सहानुभूति लहर और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बना माहौल हाशिए पर चला गया। शरद पवार की पार्टी विस चुनाव में मात्र 10 सीटें ही जीत पाई। यहां दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक राकांपा (शरद) ने 8 सीटें जीतने से गदगद पवार ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा था कि मोदी के धुआंधार प्रचार के कारण ही हम शानदार जीत हासिल कर पाए। तब पवार के हिसाब से ईवीएम भी बढ़िया काम कर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के लिए उन्होंने मोदी को श्रेय देने की जगह हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। गोया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम अलग-अलग ढंग से मैनेज की गई हों।

इन चुनावों में अगर शरद पवार की पार्टी के परफार्मेंस की ही बात की जाए तो उन्हें इस साल हुए लोकसभा चुनाव में 10.27 फीसदी वोट मिले थे और चार माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में 11.28 प्रतिशत वोट मिले। यानी करीब एक फीसदी ज्यादा। अजित पवार गुट के अलग होने के बाद शरद पवार के पास 14 विधायक बचे थे। अब चुनाव बाद भी उनके 10 विधायक हैं। यानी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब शरद पवार अपनी निराशा को जनता की हताशा के रूप में पेंट करना चाहते हैं तो यह भी एक थकी हुई चाल ही है। अगर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे सच में जनाकांक्षा के पूरी तरह विपरीत आते तो जनता ही सड़कों पर उतर आती। वैसा कहीं कुछ नहीं दिखा। ईवीएम खारिज करने को लेकर जो राजनीतिक प्रतिरोध हो रहा है, उसे भी आम जनता कौतुहल के साथ देख रही है। अलबत्ता हर चुनाव में मरकडवाडी जैसी 'प्रोटेस्ट मॉक ड्रिल' हर जगह होने लगेगी तो हमारे समूचे चुनाव सिस्टम पर गंभीर सवाल उठने लगेगा। इससे कोई समाधान शायद ही निकले, लेकिन अवांछित अराजकता जरूर फैलेगी। सुविधानुसार ईवीएम को खारिज करने और निर्वाचन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते रहने की जगह अगर पराजित पार्टियां आत्मावलोकन कर आंतरिक सुधार करें तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा।

झोपड़ी में लगी आग जिंदा जले दो मासूम

सिंगरौली में खेत में पिता के लिए खाना लेकर आए थे; खेलते-खेलते सो गए थे

सिंगरौली (नप्र)। सिंगरौली में खेत में बनी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इसमें 10 माह और 3 साल के दो बच्चे जिंदा जल गए। बेटा पिता के लिए खाना लेकर आया था। वह साथ में अपने छोटे भाई को भी ले आया था। खेलते-खेलते दोनों वहीं सो गए थे।

घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे बड़बड़ गांव की है। सूचना मिलते ही मौके पर मोरवा थाने की पुलिस, चितरंगी एसडीएम सुरेश जादव और अपर कलेक्टर भी पहुंच गए।

मृतक बच्चों के नाम बाबूलाल (3 साल) और दौली (10 माह) है। पुलिस ने बच्चों के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए है। झोपड़ी में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है।खेत में रखवाली के लिए अस्थायी झोपड़ी बनी थी। बच्चे इसमें खेलते-खेलते सो गए थे।सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे।घटना की जानकारी मिलने पर आसपास खेत में काम कर रहे लोग भी वहां पहुंच गए थे।

पिता खेत में काम कर रहे थे, अचानक भड़की आग

चितरंगी एसडीएम सुरेश जादव ने बताया कि यह गांव दुधमनिया तहसील में आता है। बच्चे के पिता सिपाहीलाल ने बताया कि मैंने अपने खलिहान में फसल की देखरेख के लिए पैरे से अस्थायी झोपड़ी बना रखी थी। दोपहर में मैं खेत में काम कर रहा था। दोनों बच्चे मेरे लिए खाना लेकर आए थे। खाना रखकर दोनों खेलते-खेलते वहीं सो गए। इस बीच हादसा हो गया। जब तक मैं कुछ कोई समझ पाता, तब तक आग में झुलस जाने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई।

पेड़ से टकराई एसयूवी, 300 मीटर दूर गिरा इंजन

उज्जैन में न्यूज एंकर समेत दो की मौत, बीजेपी नेता की एंकर बेटी और बेटा घायल

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में रविवार रात बेकाबू एसयूवी पेड़ से टकरा गई। कार का इंजन 300 मीटर दूर जा गिरा। हादसे में मक्सी के भाजपा नेता और पूर्व जिला महामंत्री के दामाद और भांजे की मौत हो गई जबकि बेटा-बेटी घायल हैं। इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे के बाद शवों को निकालने के लिए कार को कटर से काटना पड़ा। कार सवार लोग शादी में शामिल होने के लिए नागदा से मक्सी की ओर जा रहे थे। दामाद नेशनल न्यूज चैनल में बतौर एंकर काम करते थे। बेटी भी एंकर है।

परिवार में 16 दिसंबर को शादी- बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री रवि पांडेय के परिवार में 16 दिसंबर को शादी है। इसमें शामिल होने के लिए दामाद नीतीश भारद्वाज (35) गाजियाबाद से मक्सी आ रहे थे। नीतीश को नागदा जंक्शन पर रिसीव करने के लिए मक्सी से रवि पांडे के बेटे मयंक, बेटी वंशिका और भांजा अटल (16) एसयूवी से गए थे। सभी लोग नीतीश को रिसीव करने के बाद नागदा से रात करीब 12.30 बजे रवाना हुए थे।

बेकाबू होकर सड़क से उतरी एसयूवी- रविवार देर रात 1.30 बजे मक्सी से करीब 15 किमी पहले कायथा मोड़ पर कार बेकाबू होकर सड़क से उतरी और पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का इंजन 300 मीटर दूर गिरा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार की स्पीड 100 से ऊपर रही होगी। हादसे के कारण कार आगे से पूरी तरह चपटी हो गई।

एयर बैग नहीं खुलने से गई जान- एयर बैग खुलने से कार चला रहे मयंक पांडेय की जान तो बच गई लेकिन हालत गंभीर है। वहीं, दामाद नीतीश की सीट का एयर बैग नहीं खुलने से मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा नेता के 16 साल के भांजे अटल की भी जान चली गई। बेटी वंशिका गंभीर रूप से घायल है।

मध्यप्रदेश में आज से तेज ठंड

मंडला-बालाघाट समेत 4 जिलों में हल्की बारिश, भोपाल में गिरा रात का टेम्प्रेचर

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बाद यानी 10 दिसंबर से तेज ठंड का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के असर से प्रदेश में बर्फीली हवाएं आएंगी। जिनकी वजह से भोपाल-इंदौर समेत पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। सोमवार को शीत लहर चल रही थी।मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि रविवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली।

24 घंटे के दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश- मध्यप्रदेश के मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। वहीं, इसने जुड़े जिलों में बादल छाए रहे। दूसरी ओर, भोपाल समेत कई जिलों में रात के टेम्प्रेचर में गिरावट दर्ज की गई।

इसलिए बढ़ेगा ठंड का असर

उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर 12.6 किमी की ऊंचाई पर 260 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। यहां पर एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी एक्टिव हो रहा है। इस वजह से बर्फ पिघलेगी और फिर हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी। जिसका असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिलेगा।

दरअसल, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण उत्तरी इलाकों और पहाड़ों पर मौसम बदलेगा। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। ऐसा होने पर बर्फ पिघलने के बाद बर्फीली हवा मध्यप्रदेश में आएगी।

नवंबर में सर्दी तोड़ चुकी है रिकॉर्ड

नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। भोपाल में तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी पारा सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे रहा लेकिन कड़ाके की ठंड दिसंबर में पड़ेगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठिठुरेंगे। यहां कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं भी चलेंगी।

20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी

मौसम विभाग के अनुसार, 15 दिसंबर तक मौसम में ऐसा ही उतार-चढ़ाव रहेगा। कभी तेज ठंड, कभी बारिश तो कभी बादल छाए रहेंगे। कड़ाके की ठंड का दौर 20 दिसंबर से शुरू होगा, जो जनवरी तक बना रहेगा। इन्हीं 40 दिनों में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं की भी स्थिति रह सकती है। सबसे ज्यादा ठंड उज्जैन, ग्वालियर-चंबल संभाग में रहेगी। वजह यहां बर्फीली हवाएं सीधे आना है।

वर्ष 2014 से 2023 तक के ट्रेंड पर नजर डाली जाए तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में ही कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू होती है। इन पांच बड़े शहरों में पारे में सबसे ज्यादा गिरावट ग्वालियर में होती है। यहां पिछले 10 साल में एक बार टेम्परेचर 1.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। जबलपुर में यह 4.4 डिग्री और उज्जैन में 2.5 डिग्री तक रहा है। भोपाल और इंदौर में भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है।

बाइक और ऑटो की टक्कर में एक छात्र की मौत

रतलाम के बाजना में स्कूली बच्चे लेकर जा रहा था ऑटो; 7 छात्र घायल

रतलाम (नप्र)। रतलाम के बाजना में सोमवार सुबह बाइक और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। ऑटो में स्कूली बच्चे बैठे थे। टक्कर से ऑटो रिक्शा तीन पलटी खा गया। घटना में ऑटो में सवार एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य बच्चे घायल हो गए।

बाइक और ऑटो की टक्कर- घटना सुबह 8 बजे बाजना बांसवाड़ा रोड के बीच की है। ऑटो चालक गोवर्धन भोई प्रतिदिन की तरह केलकच्छ और आसपास के गांव से प्राइवेट स्कूलों को बच्चों को लेकर बाजना आ रहा था। इस दौरान केलकच्छ से 8 किमी दूर बाजना की तरफ देवड़ाहामा गांव के मोड़ पर बाइक सवार आया और ऑटो से सीधा टकरा गया।

तीन बार पलटा ऑटो, एक बच्चे की मौत- टक्कर के बाद ऑटो पलटी खा गया और घटना के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। मौके पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एंबुलेंस से घायल बच्चों को तुरंत बाजना अस्पताल लाया गया।

यहां से गंभीर घायलों को रतलाम रेफर किया गया। घटना में लुक्की पाड़ा निवासी अर्पित (10) पिता प्रकाश की मौत हो गई। चार घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

परिजन बोले- नशे में था बाइक सवार- अर्पित के काका मनीष डामर ने बताया कि ऑटो चालक प्रतिदिन गांव से बच्चों को लेकर बाजना के स्कूल आता है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे थे। बाइक सवार नशे में था। उसने सामने से आकर ऑटो को टक्कर मारी है, ऑटो में 8 से 10 बच्चे सवार थे।

मनीष ने बताया कि उसका भतीजा अर्पित बाजना के होली फैमिली स्कूल में कक्षा 5वीं का छात्र था। उसके पिता प्रकाश की गांव में किराना की दुकान है। उसका एक बड़ा भाई सुमित (12) है। घटना के बाद से परिजन सदमें में है।

7 घायल, रतलाम रेफर- मामले में बाजना थाना प्रभारी प्रेमलता खत्री ने बताया कि बाइक पर तीन लोग सवार थे। बाइक चालक ने सामने से आकर ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में 10 से 12 बच्चे सवार थे। एक की मौत हुई है, 7 बच्चे घायल हुए है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रतलाम रेफर किया है।

यह हुए घायल- हादसे में लीला (17) पिता शांतिलाल निवासी बाजना, मोहित (8) पिता राकेश, तनवी (8) पिता हरीश, रिया (8) पिता सुंदरलाल, मीनाक्षी (11) पिता विनोद, वीर (12) पिता कालू सभी निवासी केलकच्छ घायल हुए है। सभी को मेडिकल कॉलेज रतलाम में भर्ती किया है।

बाइक पर नाच रहे थे युवक- जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार ने बताया घटना उनके वार्ड क्षेत्र की है। हादसे से पहले सड़क से एक बारात जा रही थी। डीजे बज रहा था, बारात में बाइक पर नशे में सवार होकर युवक नाच रहे थे। इस दौरान ऑटो आगे निकला तो बाइक सवार एकदम सामने आ गए। उनसे बचने के चक्कर में ऑटो बाइक से टकराकर कर सड़क पर ही पलटी खा गया।

मोहन का गीता जयंती कनेक्शन !

मोहन का मंत्रालय
आशीष

एक मुख्यमंत्री और एक धार्मिक ग्रंथ के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है.. ऐसा किसी राज्य में हो न हो पर मध्यप्रदेश में तो यह कनेक्शन बन गया है..जी हां मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के अनन्य उपासक डॉ. मोहन यादव श्रीमद्भागवत गीता से कनेक्शन कह लीजिए या फिर आशीर्वाद अथवा आस्था, क्योंकि डॉ. मोहन यादव की मुख्यमंत्री पद की लॉटरी 11 दिसंबर 2023 यानी गीता जयंती के दिन ही निकली थी.. मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज दावेदारों को छोड़ उसी दिन डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ था.. और अब ठीक एक साल बाद मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के भव्य आयोजन की गूंज है... यही नहीं मध्य प्रदेश सरकार ने महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र तक में गीता महोत्सव इसका आयोजन किया है। अब इसे मुख्यमंत्री की आस्था कहें या विश्वास जिस ग्रंथ के आशीर्वाद से डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री बने वहीं अब मुख्यमंत्री ने भी श्रीमद्भागवत गीता के संदेश को जन जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री ने उठा लिया है।

कार्पोरेशन के अंगद सब पर भारी!

मध्य प्रदेश सरकार के एक अहम कॉर्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर सालों से पदस्थ दो अधिकारियों का दबदबा आज भी कायम है। मलाईदार स्थानों पर जमे दोनों अधिकारी यहां अपनी मिजाज के प्रबंध संचालक की पोस्टिंग कराने में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ बीते एक पखवाड़े में दो संचालकों का तबादला हो गया और दोनो अधिकारी जस की तस शतरंज बिछाए बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों अधिकारी ऐसा प्रबंध संचालक चाहते हैं जो यहां पर चल रही बंदर बाट की परंपरा को आगे बढ़ाएं ? राज्य शासन ने पिछले दिनों यहां एक महिला आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दे दिया था तो दोनों प्रति नियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। और मामला ऊपर तक पहुंचा तो सरकार ने ही महिला अधिकारी से अतिरिक्त चार्ज वापस ले लिया और समन्वय के अधिकारी को बैठा दिया। कॉर्पोरेशन में चर्चा है कि प्रतिनियुक्ति पर आए अंगदों के पर कब उखड़ेंगे ?

सीएम की नाराजगी से नपे एसीएस

मोहन सरकार में अपर मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी को मुख्यमंत्री की नाराजगी भारी पड़ गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी को मेन लाइन से हटा कर, अधिकारी जिसे लूप लाइन समझते हैं पदस्थ कर दिया गया है। बताया जाता है कि पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा को सार्वजनिक करने का खामियां जाए अपर मुख्य सचिव को भुगतना पड़ा है। सूत्र बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से विभागीय मंत्री की भी पटरी नहीं बैठ रही थी। पूर्व में भी एक विभाग का विभागीय अध्यक्ष रहते अधिकारी का रिकार्ड दुरुस्त नहीं रहा है।

कमलनाथ के गढ़ में शाह को शह ?

मध्य प्रदेश का अगला वन मंत्री कौन होगा इसको लेकर राजनीतिक कयासों का क्रम चल निकला है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद खाली हुए वन मंत्री का पद आरक्षित वर्ग आदिवासी कोटे में जाना है। इसी संभावना को लेकर मोहन सरकार में आदिवासी कोटे से दो मंत्रियों ने प्रयास तेज भी कर दिए हैं वही दूसरी और आदिवासी विधायक कमलेश शाह भी इस कतार में है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि शाह को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। यही वजह है कि कमलेश शाह भी के समर्थक भी शाह के मंत्री बने की प्रतीक्षा कर रहे थे यदि कमलेश शाह को मंत्री बनाया जाता है तो यादव सरकार छिंदवाड़ा में कमलनाथ के एकाधिकार को ध्वस्त करने के लिए एक और कदम बढ़ाएगी।

रिपोर्ट कार्ड, राज्य मंत्री को चिंता

प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड पेश करने की हिदायत के बाद मध्य प्रदेश की मोहन मंत्रिमंडल के मंत्रियों को आने वाले दिनों में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ सकता है। मंत्री, इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो सरकार के राज्य मंत्रियों की है कि वह अपना रिपोर्ट कार्ड कैसा पेश करें ?

बताया जाता है कि ज्यादातर मंत्रियों ने अपने विभाग के राज्य मंत्रियों को कामकाज का बटवारा ही नहीं किया। इस स्थिति में राज्य मंत्री चिंतित है कि मुख्यमंत्री यदि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड या परफॉर्मेंस 'जीरो' रहेगा। एक महिला राज्य मंत्री ने रिपोर्ट कार्ड को लेकर अपनी चिंता जताई भी है।

विधानसभा प्रमुख सचिव होगा कौन ?

मध्य प्रदेश विधानसभा के नए पीएस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा प्रमुख सचिव एपी सिंह का कार्यकाल मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले विधानसभा सचिवालय में चर्चाओं का दौर गर्म है। बताया जाता है कि प्रमोशन पर रोक से विधानसभा में प्रमुख सचिव स्तर के न केवल सचिव स्तर से अधिकारी की पात्रता वाले अफसर का अभाव है। यही वजह है कि राज्य विधानसभा में सचिव के पद पर लोकसभा सचिवालय से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी पदस्थ हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि विधानसभा में एक बार फिर न्यायिक सेवा के अधिकारी की तैनाती हो हो सकती है। इसको लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन का दौर भी चल रहा है। पूर्व में भी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रोहाणी जी के समय न्यायिक सेवा के अधिकारी राजकुमार पांडेए को प्रमुख सचिव बनाया जा चुका है।